नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 086
दि. 28.12.2025,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

मुंबई बीएमसी चुनाव: सीट बंटवारे पर गतिरोध बैठकों का दौर जारी और नामांकन की प्रक्रिया तेज

(जीएनएस)। मुंबई। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनाव के लिए आगामी वार्डों में सीट बंटवारे को लेकर राजनीतिक दलों के बीच गतिरोध जारी है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के बीच अभी तक किसी भी तरह की सहमति नहीं बन पाई है। वहीं, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और भाजपा के बीच भी सीटों को लेकर बातचीत अंतिम चरण में पहुंचने से पहले अटकी हुई है।

शनिवार को विभिन्न दलों के नेताओं के बीच लगातार बैठकें हुईं, लेकिन किसी भी दल ने अपने उम्मीदवारों की सूची का एलान नहीं किया। कुल 227 वार्डों वाली बीएमसी में सत्ता की दौड़ अपने चरम पर है और प्रत्येक दल अपनी रणनीति को लेकर सतर्क दिखाई दे रहा है। शहर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सत्ता की पैठ को देखते हुए दलों के बीच सीटों का बंटवारा संवेदनशील विषय बन गया है।

दोपहर में मनसे के नेताओं बाला नंदगांवकर, नितिन सरदेसाई और संदीप देशपांडे ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। यह बैठक महिम विधानसभा क्षेत्र के वार्डों को लेकर हुई, जिसमें दादर और प्रभादेवी जैसे प्रमुख इलाके शामिल हैं। बाला नंदगांवकर ने पत्रकारों से कहा कि कुछ वार्डों में सीटों की अदला-बदली जरूरी थी और इसी विषय को लेकर उद्धव ठाकरे से बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि यह केवल प्रारंभिक चरण की बैठक थी और एक बार फिर से चर्चा होगी, जिसके बाद सीट बंटवारे की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंचेगी। मनसे ने अब तक चुनाव अकेले लड़ा है, इसलिए सीट साझेदारी की यह प्रक्रिया उसके लिए नई और जटिल साबित हो रही है।

वहीं, भाजपा और शिंदे गुट की शिवसेना के बीच भी सीटों को लेकर गतिरोध कायम है। दोनों दलों के नेता मीरा-भायंदर, ठाणे, नवी मुंबई और कल्याण-डोंबिवली की नगरपालिकाओं को लेकर वार्ता कर रहे हैं। सत्तारूढ़ महायुति की रणनीति इस बार

भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि सभी दल बड़े पैमाने पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए प्रयासरत हैं।

नामांकन प्रक्रिया भी तेजी से जारी है। शनिवार को चौथे दिन कुल 35 नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जिससे अब तक कुल 44 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र जमा कर दिए हैं। बृहन्मुंबई महानगरपालिका की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, शहर के 23 निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालयों से अब तक कुल 10,343 नामांकन फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। यह प्रक्रिया 23 दिसंबर से शुरू हुई थी और 30 दिसंबर तक जारी रहेगी।

इस बार चुनाव की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी दलों ने सक्रिय प्रचार-प्रसार और जनसम्पर्क पर जोर दिया है। चुनाव आयोग ने भी मतदाता सूची और नामांकन प्रक्रिया की निगरानी कड़ी कर दी है। मतगणना 16 जनवरी को होगी, लेकिन उससे पहले दलों के बीच सीट बंटवारे की रणनीति और गठबंधन के समीकरण महत्वपूर्ण साबित होंगे।

विशेषज्ञों का कहना है कि बीएमसी चुनाव में किसी भी दल के लिए यह चुनौतीपूर्ण समय है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच तालमेल के साथ-साथ भाजपा और शिंदे गुट की शिवसेना के सहयोग से बनने वाले समीकरण पूरे चुनावी परिदृश्य को प्रभावित कर सकते हैं। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मतदाताओं की प्राथमिकताओं और दलों की रणनीति इस बार निर्णायक साबित हो सकती है।

इस बार चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और प्रशासनिक कार्रवाई पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। चुनाव आयोग ने सुनिश्चित किया है कि नामांकन, मतदाता सूची और चुनावी प्रचार सभी नियमों के अनुसार हो। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सीट बंटवारे के अंतिम निर्णय और गठबंधनों के फाइनल होने के बाद ही शहर के राजनीतिक परिदृश्य का असली स्वरूप सामने आएगा।

इस प्रकार, मुंबई बीएमसी चुनाव में सीटों का बंटवारा और गठबंधनों की रणनीति अभी भी उलझी हुई है। दलों के बीच बातचीत और वार्ता का दौर जारी है, जबकि नामांकन प्रक्रिया ने चुनावी उत्साह को और बढ़ा दिया है। आगामी हफ्तों में सीट बंटवारे और गठबंधन निर्णयों से ही इस चुनाव की दिशा तय होगी और शहर में नए राजनीतिक समीकरण सामने आएंगे।

तीन दशकों बाद जंगल में लौटी दहाड़ गुजरात फिर बना बाघों की धरती

(जीएनएस)। करीब तैंतीस वर्षों के लंबे अंतराल के बाद गुजरात ने वह पहचान दोबारा हासिल कर ली है, जो कभी उसकी जैव-विविधता और वन्य जीवन की शान हुआ करती थी। जिस राज्य को कभी बाघों की धरती के रूप में जाना जाता था, वह समय के थपेड़ों और बदलते पर्यावरणीय हालात में इस गौरव से वंचित हो गया था। अब राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा दाहोद जिले के रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य में एक बाघ की मौजूदगी की आधिकारिक पुष्टि के साथ ही गुजरात ने फिर से 'टाइगर स्टेट' की सूची में अपनी जगह बना ली है। यह केवल एक प्रशासनिक घोषणा नहीं, बल्कि उस उम्मीद की वापसी है जो वर्षों से वन विभाग, पर्यावरणविदों और वन्यजीव प्रेमियों के मन में जीवित थी। गुजरात का इतिहास बाघों के साथ गहराई से जुड़ा रहा है। कभी राज्य के कई वन क्षेत्रों में बाघों की अच्छी-खासी संख्या पाई जाती थी। लेकिन धीरे-धीरे शिकार, जंगलों के सिमटने और मानवीय हस्तक्षेप के कारण यह प्रजाति यहां से लगभग लुप्त हो गई। 1989 की आखिरी बाघ गणना में केवल पगचिह्न

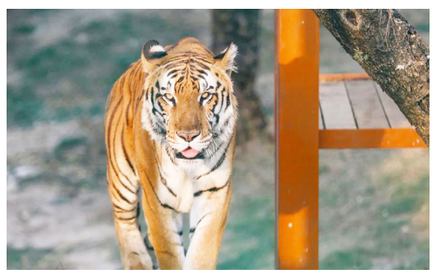

मिलने के बाद यह साफ हो गया था कि बाघ अब गुजरात के जंगलों से लगभग गायब हो चुके हैं। इसके बाद 1992 में गुजरात को आधिकारिक रूप से बाघों वाले राज्यों की सूची से बाहर कर दिया गया। उस समय यह फैसला केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि प्रकृति के एक बड़े नुकसान का संकेत था।

बीते वर्षों में कई बार उम्मीद की किरण जगी, लेकिन वह स्थायी साबित नहीं हो सकी। वर्ष 2019 में महिसागर जिले में एक बाघ की मौजूदगी ने वन्यजीव प्रेमियों में उत्साह भर दिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह बाघ मात्र पंद्रह दिनों के भीतर मृत पाया गया। यह घटना एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करती थी कि क्या गुजरात के जंगल बाघों के लिए अब भी सुरक्षित और अनुकूल हैं। इसके बाद भी वन विभाग और संरक्षण से जुड़े लोगों ने प्रयास नहीं छोड़े। जंगलों के संरक्षण, वन्यजीव गलियारों के विकास और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम लगातार चलता रहा।

अब रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य में कैमरा ट्रैप में कैद हुई बाघ की तस्वीरों और वीडियो ने तस्वीर बदल दी है। इन सबूतों की पुष्टि के बाद एनटीसीए ने न केवल बाघ की मौजूदगी को स्वीकार किया, बल्कि वर्ष 2026 की राष्ट्रीय बाघ गणना के लिए गुजरात को आधिकारिक रूप से फिर से शामिल कर लिया। यह फैसला इस बात का संकेत है कि गुजरात के जंगलों में फिर से वह क्षमता विकसित हो रही है, जहां बाघ जैसे बड़े और संवेदनशील शिकारी सुरक्षित रूप से रह सकते हैं। उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने इस उपलब्धि को हर गुजराती के लिए गर्व का क्षण बताया है। उनका कहना है कि गुजरात अब केवल शेर और तेंदुओं का ही नहीं, बल्कि बाघ का भी घर बन गया है। गिर के शेर पहले से ही राज्य की पहचान रहे हैं और तेंदुओं की भी यहां अच्छी मौजूदगी है। अब बाघ की वापसी ने गुजरात को वन्यजीव संरक्षण के मानचित्र पर एक नई मजबूती दी है। यह उपलब्धि केवल एक प्रजाति की वापसी नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि संरक्षण के प्रयास, अगर निरंतर और ईमानदारी से किए जाएं, तो प्रकृति भी सकारात्मक जवाब देती है। रतनमहल अभयारण्य की भौगोलिक स्थिति भी इस कहानी को और रोचक बनाती है। यह क्षेत्र मध्य प्रदेश की सीमाओं के पास स्थित है, जहां पहले से बाघों की आबादी मौजूद है। माना जा रहा है कि यह बाघ प्राकृतिक गलियारों के जरिए यहां तक पहुंचा है। यह तथ्य इस बात को भी रेखांकित करता है कि राज्यों के बीच जुड़े हुए वन क्षेत्र और सुरक्षित कॉरिडोर कितने जरूरी हैं।

केरल की पंचायत राजनीति में बड़ा भूचाल, मट्टाथुर में कांग्रेस का सामूहिक इस्तीफा और भाजपा के सहारे टूटा लेफ्ट का 23 साल पुराना किला

(जीएनएस)। त्रिशूर जिले की मट्टाथुर ग्राम पंचायत में केरल की स्थानीय राजनीति ने ऐसा नाटकीय मोड़ लिया है, जिसने न केवल कांग्रेस और लेफ्ट को चौंका दिया है, बल्कि भाजपा को भी अप्रत्याशित रूप से सत्ता संतुलन की निर्णायक भूमिका में ला खड़ा किया है। जिस पंचायत पर बीते 23 वर्षों से लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का दबदबा बना हुआ था, वहां अब कांग्रेस के भीतर उठे विद्रोह और भाजपा के समर्थन से सत्ता की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। कांग्रेस के सभी आठ चुने हुए सदस्यों ने एक साथ पार्टी से इस्तीफा देकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी और भाजपा के समर्थन से एक नए मोर्चे का गठन कर पंचायत की कमान अपने हाथों में ले ली।

पंचायत चुनाव के नतीजे पहले ही बेहद दिलचस्प थे। 24 सदस्यीय पंचायत में किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को 10 सीटें मिलीं, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कांग्रेस नीत गठबंधन को 8 सीटों पर संतोष करना पड़ा, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 4 सीटें हासिल हुईं और 2 निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुए। यह समीकरण ऐसा था कि पंचायत अध्यक्ष का चुनाव किसी भी दिशा में जा सकता था।

स्थिति इतनी असमंजस भरी थी कि अध्यक्ष पद के लिए लॉटरी निकालने जैसे विकल्प पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा था। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा मोड़ तब आया, जब यूडीएफ ने निर्दलीय उम्मीदवार केआर ओसेफ को समर्थन देने का फैसला किया। ओसेफ कांग्रेस के बागी माने जाते थे और उनके सहारे यूडीएफ को बहुमत की उम्मीद थी। लेकिन अध्यक्ष चुनाव से ठीक पहले ओसेफ का लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट में शामिल हो जाना कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं था। स्थानीय कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को यह विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि जिस उम्मीदवार को उन्होंने समर्थन दिया था, वही ऐन वक्त पर पाला बदल लेगा।

ओसेफ के इस कदम से नाराज होकर कांग्रेस के सभी आठ निर्वाचित सदस्यों ने सामूहिक रूप से पार्टी छोड़ने का फैसला किया। अपने इस्तीफे में इन सदस्यों ने आरोप लगाया कि स्थानीय कांग्रेस नेतृत्व ने उनके साथ अन्याय किया, पार्टी के भीतर वफादार कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई और फैसले थोपे गए। इस्तीफे के बाद इन नेताओं ने एकजुट होकर टेसी जोस कल्लरक्कल को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में समर्थन देने की घोषणा की। टेसी जोस स्वयं कांग्रेस की बागी नेता रही हैं और स्थानीय राजनीति में उनका खासा प्रभाव माना जाता है। यहां से कहानी ने और दिलचस्प मोड़ लिया, जब भाजपा ने भी इस नए बने फ्रंट को समर्थन देने का फैसला किया। भाजपा के समर्थन से टेसी जोस को कुल 12 सदस्यों का समर्थन मिला, जिससे वह पंचायत अध्यक्ष चुन ली गईं। हालांकि भाजपा का एक वोट तकनीकी कारणों से अमान्य हो गया था, फिर भी तीन वैध वोटों ने सत्ता का संतुलन बदलने में निर्णायक भूमिका निभाई। इस तरह भाजपा की मदद से कांग्रेस के बागी नेताओं ने लेफ्ट के 23 साल पुराने शासन का अंत कर दिया।

इस अप्रत्याशित राजनीतिक उलटफेर ने कांग्रेस और लेफ्ट, दोनों खेमों में खलबली मचा दी है। कांग्रेस नेतृत्व के लिए यह घटना संगठनात्मक अनुशासन और जमीनी असंतोष दोनों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। वहीं लेफ्ट के लिए यह संकेत है कि उसका पारंपरिक गढ़ भी अब पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहा। दूसरी ओर भाजपा ने इस घटनाक्रम को लोकतांत्रिक जनादेश का सम्मान बताते हुए संतुलित प्रतिक्रिया दी है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि केरल जैसे राज्य में यह घटना भाजपा के लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त का संकेत है। इस्तीफा देने वाले कांग्रेस सदस्यों में मिनिमोल, श्रीजा, सुमा एंटनी, अक्षय संतोष, प्रिंटो पल्लीपरंबन, सीजी राजेश, सीबी पॉलोज और नूरजहां नवाज शामिल हैं। इन सभी ने एक स्वर में कहा है कि उनका फैसला किसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से नहीं, बल्कि स्थानीय राजनीति में सम्मान और न्याय की लड़ाई से जुड़ा है। फिलहाल कांग्रेस ने इन आठ सदस्यों के खिलाफ कोई औपचारिक कार्रवाई नहीं की है, लेकिन आने वाले दिनों में पार्टी के भीतर इस मुद्दे पर मंथन तेज होने की संभावना है।

कानून की जकड़ से आज़ादी तक: हाईकोर्ट की सख़्त टिप्पणी के बीच पुझल जेल से बाहर आए 'सुवुक्कू' शंकर

(जीएनएस)। चेन्नई की पुझल सेंट्रल जेल के बाहर शनिवार को उस समय माहौल बदला-बदला सा दिखा, जब यूट्यूबर और वीडियो पत्रकार के रूप में चर्चित 'सुवुक्कू' शंकर तीन महीने की अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा हुए। मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के बाद जैसे ही वह जेल के मुख्य द्वार से बाहर निकले, यह सिर्फ़ एक व्यक्ति की रिहाई नहीं थी, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के दुरुपयोग और सत्ता-प्रशासन के रिश्ते पर फिर से बहस छेड़ने वाला क्षण भी बन गया। शंकर को 13 दिसंबर को उनके चेन्नई स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया था। उन पर एक फिल्म निर्माता के साथ मारपीट और जबरन वसूली जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जेल से बाहर आते ही उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर अपनी तस्वीर साझा करते हुए लिखा—"क्या आपने सोचा था कि मैं हार जाऊंगा?" यह एक वाक्य उनके समर्थकों के लिए संदेश था और आलोचकों के लिए चुनौती।

इस रिहाई के पीछे कानूनी प्रक्रिया जितनी अहम रही, उतनी ही अहम वह टिप्पणी भी रही, जो मद्रास हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच ने सुनवाई के दौरान की। शंकर की मां ए. कमला ने अपने बेटे की गंभीर स्वास्थ्य स्थिति का हवाला देते हुए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। उन्होंने कहा कि शंकर हृदय रोग और मधुमेह से पीड़ित हैं और जेल में उनका इलाज ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एस.एम. सुब्रमणियम और जस्टिस पी. धनबल की पीठ ने 26 दिसंबर 2025 से 25 मार्च 2026 तक, यानी पूरे 12 हफ्तों के लिए अंतरिम जमानत मंजूर कर दी। अदालत ने जेल अधीक्षक के समक्ष एक लाख रुपये के निजी मुचलके की शर्त भी रखी, जिसे पूरा करने के बाद शंकर की रिहाई संभव हो सकी।

हालांकि यह आदेश सिर्फ़ स्वास्थ्य के आधार पर दी गई राहत तक सीमित नहीं रहा। अदालत की टिप्पणियों ने इस मामले को कहीं अधिक व्यापक बना दिया। हाईकोर्ट ने खुले शब्दों में कहा कि यह समझना कठिन है कि एक ही यूट्यूब पत्रकार को बार-बार कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जेल भेजे जाने की नौबत क्यों आ रही है। इस स्थिति से यह संदेह पैदा होता है कि कहीं वह सत्तारूढ़ सरकार या व्यवस्था की आलोचना करने की वजह से निशाने पर तो नहीं हैं। अदालत ने याद दिलाया कि 'सुवुक्कू' शंकर के खिलाफ पहले भी गुंडा एक्ट लगाया गया था, जिसे अगस्त 2024 में मद्रास हाईकोर्ट ने ही रद्द कर दिया था। इसके तुरंत बाद दूसरा हिरासत आदेश पारित होना न केवल असामान्य है, बल्कि इससे कानून की मंशा और उसके दुरुपयोग पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून की प्रक्रिया का इस्तेमाल किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने या उसे बार-बार परेशान करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। किसी नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को केवल इसलिए सीमित करना कि वह सत्ता से असहमति रखता है या आलोचनात्मक सवाल उठाता है, लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। हाईकोर्ट की टिप्पणी में यह साफ झलका कि न्यायपालिका इस मामले को सिर्फ़ एक आपराधिक प्रकरण के रूप में नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समान प्रयोग के बड़े संदर्भ में देख रही है। शंकर की रिहाई के बाद तमिलनाडु के राजनीतिक और मीडिया जगत में इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज़ हो गई हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि 'सुवुक्कू' शंकर लंबे समय से सत्ता और प्रशासन से जुड़े मुद्दों पर तीखे सवाल उठाते रहे हैं और इसी वजह से वह लगातार कानूनी दबाव का सामना कर रहे हैं।

प्रीमियर की चमक में मातम: 'पुष्पा-2' भगदड़ मामले में अल्लू अर्जुन समेत 23 पर आरोप-पत्र

(जीएनएस)। हैदराबाद की चकाचौंध भरी फिल्मी दुनिया में उस दिन जश्न का माहौल था, जब बहुप्रतीक्षित फिल्म 'पुष्पा-2' के प्रीमियर का आयोजन किया गया। संध्या थिएटर के बाहर हजारों प्रशंसकों की भीड़ अपने पसंदीदा सितारे अल्लू अर्जुन की एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़ी थी। लेकिन यह उत्साह कुछ ही पलों में अफरा-तफरी, चीख-पुकार और मातम में बदल गया। उसी भगदड़ की घटना में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई और उसका आठ वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। अब इसी मामले में हैदराबाद पुलिस ने अभिनेता अल्लू अर्जुन समेत 23 लोगों के खिलाफ अदालत में आरोप-पत्र दाखिल कर दिया है, जिससे यह मामला केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि जिम्मेदारी और लापरवाही के बड़े सवालों से जुड़ गया है। पुलिस द्वारा दाखिल आरोप-पत्र में थिएटर प्रबंधन को मुख्य आरोपी बताया गया है। दस्तावेजों के अनुसार, कार्यक्रम के आयोजन, सुरक्षा इंतजामों और भीड़ नियंत्रण में गंभीर चूक सामने आई है। अल्लू अर्जुन को इस मामले में आरोपी संख्या-11 के रूप में नामित किया गया है। पुलिस का कहना है कि प्रीमियर के दौरान अभिनेता की मौजूदगी और उनके स्वागत की व्यवस्था ने भीड़ को और अधिक उत्तेजित कर दिया, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे। चार दिसंबर 2024 की उस शाम, जब फिल्म की स्क्रीनिंग शुरू होने से पहले प्रशंसक बेकाबू हुए, तब हालात संभालने के लिए न तो पर्याप्त पुलिस बल था और न ही थिएटर प्रशासन के पास कोई प्रभावी योजना।

घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जैसे ही यह खबर फैली कि अल्लू अर्जुन थिएटर पहुंचने वाले हैं, भीड़ अचानक आगे की ओर धकेलने लगी। संकरे रास्ते, अव्यवस्थित प्रवेश द्वार और बैरिकेडिंग की कमी ने स्थिति को और भयावह बना दिया। कुछ ही मिनटों में भगदड़ मच गई। इसी अफरा-तफरी में 35 वर्षीय महिला गिर पड़ी और भीड़ के पैरों तले कुचल गई। जब तक लोग समझ पाते कि क्या हो रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका मासूम बेटा भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। जांच के दौरान सामने आया कि थिएटर प्रबंधन ने अपेक्षित सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया था। भीड़ की संख्या का सही आकलन नहीं किया गया, आपातकालीन निकास मार्गों को स्पष्ट रूप से चिन्हित नहीं किया गया और निजी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी नाकाफी थी। पुलिस का आरोप है कि आयोजकों और संबंधित लोगों ने यह जानते हुए भी कि फिल्म के सुपरस्टार की मौजूदगी भारी भीड़ खींचेगी, पर्याप्त इंतजाम नहीं किए।

अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी ने इस मामले को और अधिक चर्चा में ला दिया था। हालांकि बाद में उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत राहत मिली, लेकिन आरोप-पत्र में उनका नाम शामिल होना यह संकेत देता है कि जांच एजेंसियां किसी भी स्तर पर लापरवाही को नजरअंदाज नहीं करना चाहतीं। पुलिस का तर्क है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले बड़े सितारों की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वे आयोजकों से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करें, क्योंकि उनकी मौजूदगी से भीड़ का स्वरूप बदल जाता है।

यह मामला केवल एक अभिनेता या थिएटर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे मनोरंजन उद्योग और सार्वजनिक आयोजनों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। देशभर में फिल्म प्रीमियर, संगीत कार्यक्रम और धार्मिक या राजनीतिक आयोजन अक्सर भारी भीड़ को आकर्षित करते हैं।

संपादकीय

सेंगर की रिहाई से उठे सवाल

उन्नाव दुराचार मामले में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को सशर्त जमानत दिए जाने के खिलाफ शुक्रवार को पीड़िता की मां समेत कई लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट के सामने प्रदर्शन किया। वे दोषियों को कड़ी सजा दिए जाने की मांग कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुचर्चित उन्नाव रेप केस के दोषी पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सशर्त जमानत दे दी थी। जिसके बाद फैसले को लेकर सवाल उठाये जा रहे हैं। पीड़िता की मां इस जमानत को रद्द करने और शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात कहती रही हैं। वे अपने पति के हत्यारों को फांसी देने की गुहार लगाती नजर आईं। विपक्षी नेता भी आरोप लगाते रहे हैं जिस तरह तकनीकी आधार पर दोषी को छूट दी गई है, उसमें न्यायिक प्रणाली के लिये गलत परंपरा विकसित होगी। जिससे पीड़िता के परिवार का ही नहीं, बल्कि देश की महिलाओं का भरोसा भी टूटेगा। दरअसल, वर्ष 2017 में हुए इस बहुचर्चित मामले में पूर्व विधायक को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी गई थी। जिसे हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ पिछले दिनों जमानत दे दी। जिसके खिलाफ पीड़ित पक्ष और कतिपय महिला संगठन मुखर हुए हैं। बल्कि इस मामले की सर्वाइवर का कहना था कि यदि दोषी व्यक्ति जेल से बाहर होगा तो सुरक्षा के लिये मुझे जेल भेज दिया जाए। उल्लेखनीय है कि सजा मिलने के छह साल बाद हाईकोर्ट की एक बैंच ने उसकी सजा निलंबित कर दी थी। पूर्व विधायक को 15 लाख रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के तीन जमानतदार पेश करने का निर्देश दिया था। सजा निलंबित होने के कुछ ही घंटों के बाद पीड़िता व कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन किया था। उनका आरोप था कि उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दोषी को जमानत दी गई है।

पीड़ित पक्ष का आरोप था कि दोषी व्यक्ति जेल से बाहर रहेगा तो उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इस मामले में विपक्षी राजनीतिक दलों की भी तल्ख प्रतिक्रियाएं आई हैं। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता ने इस जमानत को निराशाजनक बताया। उल्लेखनीय है कि इस अपराध के सामने आने में दस माह लगे थे। मामले के तूल पकड़ने पर पीड़िता के पिता पर हमला हुआ था। उन्हें बाद में जेल भेज दिया गया था और पुलिस हिरासत में रहस्यमय ढंग से उनकी मृत्यु हो गई थी। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि जमानत की अवधि में सेंगर सर्वाइवर के पांच किमी के दायरे में नहीं आएंगे और दिल्ली में ही रहेंगे। उसे हर सोमवार पुलिस के समक्ष रिपोर्ट करने का भी निर्देश दिया गया है। साथ ही यह भी कि किसी भी शर्त के उल्लंघन में जमानत रद्द कर दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि सेंगर ने ट्रायल कोर्ट में दुराचार के लिये दोषी ठहराने वाले फैसले को चुनौती दी थी। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद उसे गिरफ्तार किया गया था, उसके खिलाफ बलात्कार, अपहरण और आपराधिक धमकी के आरोप लगे। साथ ही पोक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हुआ था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़े चार मामलों की सुनवाई दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी। इस बीच रायबरेली जाते समय पीड़िता की कार को एक ट्रक ने टक्कर मारी थी, जिसमें उनकी दो मौसियों की मौत हो गई थी। यही वजह है कि ट्रायल कोर्ट ने दुराचार के मामले में सेंगर को दोषी ठहराते हुए न केवल आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी बल्कि निर्देश दिया था कि सीबीआई सर्वाइवर और उसके परिवार के जीवन व स्वतंत्रता की सुरक्षा भी सुनिश्चित करे। इतना ही नहीं ट्रायल कोर्ट ने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सेंगर के सार्वजनिक सेवक होने के बावजूद अपराध करने को अनैतिक बताया था। जो जनता का विश्वास तोड़ने वाला है। वहीं कानून के जानकार मानते हैं कि पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में भी सेंगर को दस साल की सजा हुई थी, अतः अभी उसके जेल से बाहर आने की संभावना नहीं है। लेकिन इस जमानत के फैसले ने न्याय व अन्याय के सवाल को फिर से सवालों के घेरे में खड़ा किया है।

राष्ट्रमंडल खेलों के बहाने क्या अहमदाबाद बन पाएगा कर्णावती

> गुजरात के इस प्रमुख नगर को पहले कर्णावती के ही नाम से जाना जाता था। दस्तावेजों के मुताबिक, इसकी स्थापना 11वीं सदी में सोलंकी शासक कर्णदेव ने की थी। उसी के नाम के चलते इसे कर्णावती कहा जाता था। लेकिन बाद में वहां सुल्तान अहमद शाह ने आक्रमण किया और कब्जे के बाद उसने इस शहर के बगल में 1411 में 'अहमदाबाद' बसाया।

राष्ट्रमंडल खेलों के शताब्दी वर्ष के आयोजन की जिम्मेदारी अहमदाबाद को मिलने के बाद एक बार फिर उसका नाम बदलकर कर्णावती करने को लेकर सोशल मीडिया पर मांग तेज हो गई है। तर्क दिया जा रहा है कि राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन यानी साल 2030 तक गुजरात की पहली राजधानी को कर्णावती के नाम से जाना चाहिए। यह पहला मौका नहीं है, जब इस शहर का नाम बदलने की मांग हो रही है। जब साल 2018 में गुजरात के सहोदर राज्य महाराष्ट्र की तत्कालीन सरकार ने कई शहरों के नाम बदले, तब भी यह मांग उठी थी। लेकिन तब इसे अस्वीकार कर दिया गया था। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का जोर भारत के प्राचीन रूप और नाम पर रहा है, फिर गुजरात की सत्ता पर भाजपा तकरीबन तीन दशक से काबिज है, इसकी वजह से शहर को पुराने नाम की पहचान दिलाने की चाहत रखने वाले रह-रहकर मांग करते रहे हैं। गुजरात के इस प्रमुख नगर को पहले कर्णावती के ही नाम से जाना जाता था। दस्तावेजों के मुताबिक, इसकी स्थापना 11वीं सदी में सोलंकी शासक कर्णदेव ने की थी। उसी के नाम के चलते इसे कर्णावती कहा जाता था। लेकिन बाद में वहां सुल्तान अहमद शाह ने आक्रमण किया और कब्जे के बाद उसने इस शहर के बगल में 1411 में 'अहमदाबाद' बसाया। कर्णावती नाम करने की मांग के पीछे इस शहर को उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ों से फिर से जोड़ने की चाहत से प्रेरित है। कुछ वैसे ही, जैसे उत्तर प्रदेश में फैजाबाद को बदलकर अयोध्या, मुगलसराय को बदलकर दीनदयाल उपाध्याय नगर, इलाहाबाद को बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद गौरवशाली अतीत से जुड़ने और उसकी संज्ञाओं को बहाल करने का दौर तेज हो गया है। अयोध्या में राममंदिर, वाराणसी में काशी-विश्वनाथ कॉरीडोर और उज्जैन में महाकाल कॉरीडोर बनने के बाद पुनरूत्थानवादी सोच और प्रक्रिया को और बल मिला है। ऐसे में अहमदाबाद को पुराने कर्णावती नाम से जानने-पुकारने की इच्छा होना अचरज की बात नहीं है।

कर्णावती नाम करने को लेकर कभी इसी शहर के एलिसब्रिज से विधायक और अब गांधीनगर से सांसद गृहमंत्री अमित शाह और अहमदाबाद पूर्व से लोकसभा सदस्य रहे हंसमुख भाई पटेल नकार चुके हैं। यह बात और है कि कभी हसमुख पटेल खुद भी कर्णावती नाम करने के लिए अभियान चला चुके थे। उन्होंने खुद 1995 और 2000 में नाम बदलने के लिए आवेदन भी दिया था, लेकिन इसे नकार दिया गया था। बाद में उन्होंने ही 2005 में शहर को हेरिटेज सिटी यानी विरासत शहर का दर्जा देने की मांग की थी। इसके बाद वे कर्णावती नाम किए जाने की मांग से पीछे हट गए थे। तब उन्होंने कहा था कि अब अगर अहमदाबाद शहर का नाम बदलकर कर्णावती किया गया तो उसे वर्ल्ड हेरीटेज सिटी का दर्जा मिलना मुश्किल हो जाएगा। साल 2018 में गुजरात के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा था कि राज्य सरकार अहमदाबाद का नाम बदलकर कर्णावती करने पर विचार कर रही है। राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रुपाणी भी ऐसा कहते रहे। तब उनकी राय सामने आने के बाद अहमदाबाद के इतिहास को लेकर नई बहस छिड़ गई थी। इसी तरह जब से अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन का जिम्मा मिला है, एक बार फिर यही बहस तेज हो गई है।

अहमदाबाद ही कर्णावती था, इसकी जानकारी कई ऐतिहासिक पुस्तकों में मिलती है। ऐसी ही एक पुस्तक है, गुजरात विश्वविद्यालय में फ़ारसी के प्रमुख रहे छोटूभाई नायक की किताब 'हिस्ट्री ऑफ़ इस्लामिक सल्तनत इन गुजरात'। इसमें छोटू भाई नायक ने बताया है कि गुजरात के पहले स्वतंत्र शासक मुज़फ़्फ़रशाह ने अपने चार लड़कों को दरकिनार करते हुए अपने पोते अहमद शाह को अनहिलवाद के सिंहासन पर बैठा दिया था। जिसे आज हम पाटन के नाम से जानते हैं। इसी मुज़फ़्फ़र शाह के पांच बेटे थे, फ़िरोज़ ख़ान, हैबत ख़ान, सादत ख़ान, तातार ख़ान और शेर ख़ान। जिस अहमद शाह ने अहमदाबाद बसाया, वह तातार ख़ान का बेटा था। अहमद शाह के चाचाओं को इस बात का मलाल रहा कि राज्य में उन्हें हिस्सा नहीं मिला। गुजरात के इतिहास पर अंग्रेज लेखक एडवर्ड क्लाइव बेले की मशहूर किताब है, 'द लोकल मौह्मडन डायनेस्टीज़ः गुज़रात'। इसमें उन्होंने मुजफ्फरशाह परिवार के संघर्ष पर प्रकाश डाला है। इस पुस्तक में बताया गया है कि फ़िरोज़ ख़ान का बेटा और अहमद शाह का चचेरा भाई मौदूद तब बड़ोदा का गवर्नर था। मौदूद ने अपने पिता फ़िरोज़ ख़ान के साथ मिलकर अहमद शाह के ख़िलाफ़ बग़ावत छेड़ने की तैयारी की और अपने साथ अमीर मुसलमानों को मिलाना शुरू किया। इस पुस्तक के मुताबिक, तत्कालीन दो हिंदू सरदारों, जीवनदास खत्री और प्रयागदास ने भी फ़िरोज़ ख़ान का साथ दिया। छोटू भाई शाह की पुस्तक के अनुसार, मालवा के सुल्तान हुशांग शाह ने भी अहमद शाह के ख़िलाफ़ बग़ावत में फ़िरोज़ ख़ान का साथ दिया था। अहमद शाह के ख़िलाफ़ खड़ी हो रही सेना की अगुआई मौदूद के हाथ थी, उसने जीवनदास को अपना वज़ीर घोषित कर दिया। जीवनदास ने पाटन पर हमले की सलाह दी। लेकिन कई ने इसका विरोध किया। कुछ लोग ऐसे भी रहे, जिन्होंने समझौते का प्रस्ताव रखा था। लेकिन दोनों पक्षों में विवाद इतना बढ़ा कि कुछ लोगों ने पलट कर अहमद शाह से मिल गए। बहरहाल बाद में संघर्ष हुआ, जिसमें जीवनदास खत्री मारा गया।

इसके बाद मौदूद को मजबूरी में खंबात का रूख करना पड़ा। वहां सूरत के शेख मलिक और रेंडर से उसकी मुलाकात हई। इस बीच अहमद शाह उसका पीछा करता रहा और उसने जल्द ही मौदूद को गिरफ्तार करके भरूच किले को घेर लिया। बाद में सुल्तान को मौदूद पर दया आ गई और उसने मौदूद को रिहा करके वापस लौट गए। पाटन लौटते वक्त अहमदशाह ने साबरमती के किनारे असावल नामक कस्बे के पास डेरा डाला था। जिसके प्रमुख आशा भील थे। इसका जिक्र फारसी भाषा में लिखी अली मुहम्मद ख़ान की किताब मिरात-ए-अहमदी में जिक्र मिलता है। छोटूभाई नायक भी अपनी किताब में यही बात लिखते हैं। जहां सुल्तान रुका था, वहीं उसने नया शहर बसाने का फ़ैसला किया।

इसके बाद सुल्तान अपनी सेना लेकर आए जिसके बाद असावल के सरदार आशा भील को अपना क़स्बा छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन आशा भील इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन अहमदशाह की सेना के सामने वह टिक नहीं पाए और उन्हें पलायन करना पड़ा। फिर अहमदाबाद शहर की नींव 1411 के फरवरी-मार्च महीने में रखी गई। एक दावा यह भी है कि अहमद शाह ने अपने पीर हज़रत शेख़ अहमद खट्टू गंज बख़्श की सलाह पर अहमदाबाद शहर बसया। लेकिन एक और लेखक खान बहादुर ने अपनी पुस्तक 'हिस्ट्री ऑफ़ गुजरात' में लिखा है कि अहमद शाह ने चार अहमदों, जिनमें एक उनके गुरू भी थे, के नाम पर शहर का नाम अहमदाबाद रखा।

गुजरात के जाने-माने पत्रकार अच्युत याज्ञनिक और उनकी साथी सुचित्रा सेठ ने अपनी किताब 'अहमदाबाद फ्रॉम रॉयल सिटी टू मेगा सिटी' में अहमदाबाद, कर्णावती और असावल की चर्चा की है। अहमदाबाद को अरबी और फ़ारसी इतिहासकारों ने इसे असावल कहा है, जबकि संस्कृत और प्राकृत साहित्य में इसे आशापल्ली कहा गया है। दसवीं सदी में भारत आए ईरानी इतिहासकार अल-बरूनी ने भी असावल नाम की जगह का जिक्र किया है। इसी तरह 1039 में लिखी जैन आचार्य जिनेश्वरसुरी की पुस्तक 'निर्वाणलीलावतीकथा' में अशापल्ली का ज़िक्र है।साफ है कि अहमदाबाद के पहले वहां आशापल्ली या असावल नाम की जगह थी या शहर था। इसके करीब 1304-05 में लिखी अपनी पुस्तक 'प्रबंधचिंतामणि' में जैन आचार्य मेरुतुंडाछय ने कर्णावती का उल्लेख किया है। इसी किताब में जिक्र मिलता है कि पाटन के राजा कर्णदेव ने आशापल्ली पर कब्जा आशा भील को हराने के बाद किया और यहां पहले कोछराब देवी का मंदिर स्थापित करके यहां रहना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने यहां कर्णेश्वर महादेव का मंदिर बनाया भी बनाया। इसके बाद उन्होंने कर्णा सागर बनवाया और कर्णावती पुरी को बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया।

इन्हीं ऐतिहासिक साक्ष्यों के ही आधार पर अहमदाबाद को कर्णावती करने की मांग उठती रही है। राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के बहाने एक बार फिर यह मांग उठ रही है। राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन की तैयारी में यह शहर सजेगा, उसकी गरिमा में चार-चांद लगेगा। इसी बहाने अगर उसका इतिहास लौट आए तो इसे कम से कम इतिहास, संस्कृति और गौरवपूर्ण अतीत से स्नेह करने वाले लोगों को भला क्यों एतराज होगा। देखना यह है कि गरिमा और गौरव पूर्ण अतीत की ओर लौटने की यह यात्रा कब तक पूरी हो पाती है।

प्रेरणा

धैर्य की परीक्षा और सफलता का रहस्य

प्राचीन मगध की धरती पर स्थित एक शांत गुरुकुल में आचार्य ज्ञानसागर जी का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता था। वे केवल शास्त्रों के ज्ञाता ही नहीं, बल्कि जीवन को गहराई से समझने वाले ऐसे गुरु थे, जो अपने शिष्यों को पुस्तकीय ज्ञान से अधिक व्यवहारिक बुद्धि और मानसिक दृढ़ता सिखाने में विश्वास रखते थे। उनके लिए शिक्षा का अर्थ था—मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाना, ताकि वह जीवन की हर परीक्षा में स्थिर रह सके। गुरुकुल में दूर-दूर से आए शिष्य रहते थे, जो विद्या के साथ-साथ अनुशासन, सेवा और संयम का पाठ भी सीखते थे।

एक दिन आचार्य ने निश्चय किया कि वे अपने शिष्यों के धैर्य और आस्था की वास्तविक परीक्षा लेंगे। उस दिन का वातावरण सामान्य ही था। प्रातःकालीन अध्ययन के बाद सत्र समाप्त हुआ तो आचार्य ने सभी शिष्यों को सभा में बुलाया। उनके सामने बांस की बनी हुई टोकरियाँ रखी थीं। आचार्य ने शांत स्वर में कहा कि गुरुकुल की सफाई के लिए नदी से जल लाना आवश्यक है और प्रत्येक शिष्य को इन टोकरियों में पानी भरकर लाना होगा। यह सुनते ही शिष्यों के चेहरों पर आश्चर्य और असमंजस के भाव उभर आए। सभी जानते थे कि बांस की टोकरियों में असंख्य छिद्र होते हैं, जिनमें जल टिक ही नहीं सकता।

फिर भी, गुरु की आज्ञा थी, इसलिए किसी ने प्रश्न नहीं किया। मन ही मन कई शिष्य सोचने लगे कि यह कार्य असंभव है। कुछ के मन में यह विचार भी आया कि शायद आचार्य हमें व्यर्थ का श्रम दे रहे हैं। परंतु गुरु की बात टालना किसी के लिए संभव नहीं था। सभी शिष्य टोकरियाँ उठाकर नदी की ओर चल पड़े। नदी के किनारे पहुँचकर उन्होंने जल भरने का प्रयास किया। जैसे ही टोकरी को पानी में डाला, जल तुरंत रिसकर बाहर निकलने लगा। बार-बार कोशिश करने पर भी परिणाम वही रहा। कुछ समय बाद कई शिष्य निराश हो गए। उन्होंने यह मान लिया कि यह कार्य हो ही नहीं सकता।

धीरे-धीरे शिष्य गुरुकुल की ओर खाली टोकरियों के साथ लौटने लगे। उनके मन में असंतोष और थकान थी। वे सोच रहे थे कि जब कार्य असंभव है तो बार-बार प्रयास करने का क्या लाभ। किंतु उन्हीं शिष्यों के बीच एक शिष्य ऐसा भी था, जिसका मन इन विचारों से अलग था। उसका नाम बहुत साधारण था, पर उसका भाव असाधारण था। वह गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा रखता था। उसके मन में केवल एक ही विचार था—जब गुरु ने यह कार्य दिया है, तो उसमें अवश्य कोई गूढ़ अर्थ छिपा होगा। असंभव दिखने वाला कार्य भी संभव हो सकता है, यदि प्रयास जारी रखा जाए।

वह शिष्य बार-बार टोकरी को नदी में डुबोता रहा। हर बार पानी निकल जाता, फिर भी उसने हार नहीं मानी। सूर्य धीरे-धीरे आकाश में ऊपर चढ़ने लगा। दोपहर का समय आ गया, लेकिन वह शिष्य वहीं डटा रहा। उसके हाथ थक चुके थे, वस्त्र भीग चुके थे, मन में कभी-कभी निराशा की हल्की-सी लहर उठती, पर वह उसे तुरंत गुरु की स्मृति से शांत कर लेता। उसे विश्वास था कि निरंतर प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा।

समय के साथ एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। बांस की टोकरियाँ लगातार पानी में रहने से पूरी तरह भीग गईं। बांस की तीलियाँ फूलने लगीं और उनके बीच के सूक्ष्म छिद्र धीरे-धीरे बंद होने लगे। शिष्य ने जब पुनः टोकरी को पानी में भरा, तो इस बार पानी पहले की तुलना में कम रिसा। यह देखकर उसके मन में नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने और अधिक लगन से प्रयास जारी रखा। शाम होने तक वह क्षण आ गया, जब टोकरी पूरी तरह पानी से भर गई और पानी बाहर नहीं निकला।

सूर्यास्त के समय वह शिष्य भारी टोकरी उठाकर गुरुकुल की ओर लौटा। उसके चेहरे पर थकान थी, पर उससे भी अधिक संतोष और शांति थी। जब वह आचार्य ज्ञानसागर जी के सामने पहुँचा और जल से भरी टोकरी रखी, तो आचार्य के मुख पर मंद मुस्कान फैल गई। अन्य शिष्य यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें अपनी जल्दबाजी और निराशा पर ग्लानि होने लगी।

आचार्य ने सभी शिष्यों की ओर देखते हुए कहा कि उन्होंने जानबूझकर कठिन और असंभव-सा दिखने वाला कार्य सौंपा था। इसका उद्देश्य यह देखना था कि कौन केवल परिस्थितियों को देखकर हार मान लेता है और कौन विश्वास, धैर्य और निरंतर प्रयास से समाधान खोजता है। उन्होंने समझाया कि जीवन में भी कई बार ऐसे कार्य आते हैं, जो प्रारंभ में असंभव प्रतीत होते हैं। यदि मनुष्य पहली असफलता में ही हार मान ले, तो सफलता उससे हमेशा दूर ही रहती है। पर जो व्यक्ति धैर्य रखता है, प्रयास करता रहता है और अपने गुरु, अपने लक्ष्य या अपने विश्वास पर अडिग रहता है, वही अंततः सफल होता है।

उस दिन गुरुकुल के सभी शिष्यों ने एक अमूल्य शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने जाना कि सफलता अचानक नहीं मिलती, बल्कि वह निरंतर प्रयास का परिणाम होती है। धैर्य वह शक्ति है, जो असंभव को भी संभव बना देती है। आचार्य ज्ञानसागर जी का यह प्रयोग शिष्यों के जीवन में गहराई से अंकित हो गया और वे जीवनभर इस सीख को अपने आचरण में उतारते रहे। यह कथा आज भी यही संदेश देती है कि सच्ची सफलता केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि धैर्य, विश्वास और निरंतर प्रयास से प्राप्त होती है।

त्याग और बलिदान के सच्चे प्रतीक गुरु गोबिंद सिंह

सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व इस वर्ष 27 दिसंबर को मनाया जा रहा है। हिन्दू कैलेंडर के अनुसार गुरु गोबिंद सिंह का जन्म 1667 ई. में पौष माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को 1723 विक्रम संवत् को पटना साहिब में हुआ था। प्रतिवर्ष इसी दिन गुरु गोबिंद सिंह का प्रकाशोत्सव मनाया जाता है। गुरु गोबिंद सिंह जी को बचपन में गोबिंद राय के नाम से जाना जाता था। उनके पिता गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। पटना में रहते हुए गुरू जी तीर-कमान चलाना, बनावटी युद्ध करना इत्यादि खेल खेला करते थे, जिस कारण बच्चे उन्हें अपना सरदार मानने लगे थे। पटना में वे केवल 6 वर्ष की आयु तक ही रहे और सन् 1673 में सपरिवार आनंदपुर साहिब आ गए। यहीं पर उन्होंने पंजाबी, हिन्दी, संस्कृत, बृज, फारसी भाषाएं सीखने के साथ घुड़सवारी, तीरंदाजी, नेजेबाजी इत्यादि युद्धकलाओं में भी महारत हासिल की। कश्मीरी पंडितों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए उनके पिता और सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी द्वारा नवम्बर 1975 में दिल्ली के चांदनी चौक में शीश कटाकर शहादत दिए जाने के बाद मात्र 9 वर्ष की आयु में ही गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों के 10वें गुरू पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली और खालसा पंथ के संस्थापक बने। शौर्य, साहस, त्याग और बलिदान के सच्चे प्रतीक तथा इतिहास को नई धारा देने वाले अद्वितीय, विलक्षण और अनुपम व्यक्तित्व के स्वामी गुरु गोबिंद सिंह जी को इतिहास में एक विलक्षण क्रांतिकारी संत व्यक्तित्व का दर्जा प्राप्त है। वे कहते थे कि किसी भी व्यक्ति को न किसी से डरना चाहिए और न ही दूसरों को डराना चाहिए। उन्होंने समाज में फैले भेदभाव को समाप्त कर समानता स्थापित की थी और लोगों में आत्मसम्मान तथा निडर रहने की भावना पैदा की। एक आध्यात्मिक गुरु होने के साथ-साथ वे एक निर्भयी योद्धा, कवि, दार्शनिक और उच्च कोटि के लेखक भी थे। उन्हें विद्वानों का संरक्षक भी माना जाता था। दरअसल कहा जाता है कि 52 कवियों और लेखकों की उपस्थिति सदैव उनके दरबार में बनी रहती थी और इसीलिए उन्हें 'संत सिपाही' भी कहा जाता था। उन्होंने स्वयं कई ग्रंथों की रचना की थी।

'बिचित्र नाटक' को गुरु गोबिंद सिंह की आत्मकथा माना जाता है, जो उनके जीवन के विषय में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। यह 'दशम ग्रंथ' का एक भाग है, जो गुरु गोबिंद सिंह की कृतियों के संकलन का नाम है। इस दशम ग्रंथ की रचना गुरू जी ने हिमाचल के पोंटा साहिब में की थी। कहा जाता है कि एक बार गुरु गोबिंद सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर हिमाचल प्रदेश से गुजर रहे थे और एक स्थान पर उनका घोड़ा अपने आप आकर रुक गया। उसी के बाद से उस जगह को पवित्र माना जाने लगा और उस जगह को पोंटा साहिब के नाम से जाना जाने लगा। दरअसल 'पोंटा' शब्द का अर्थ होता है 'पांव' और जिस जगह पर घोड़े के पांव अपने आप थम गए, उसी जगह को पोंटा साहिब नाम दिया गया। गुरु जी ने अपने जीवन के चार वर्ष पोंटा साहिब में ही बिताए, जहां अभी भी उनके हथियार और कलम रखे हैं।

1699 में बैसाखी के दिन तख्त श्री केसगढ़ साहिब में कड़ी परीक्षा के बाद पांच सिखों को 'पंज प्यारे' चुनकर गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, जिसके बाद प्रत्येक सिख के लिए कृपाण या श्रीसाहिब धारण करना अनिवार्य कर दिया गया। वहीं पर उन्होंने 'खालसा वाणी' भी दी, जिसे 'वाहे गुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह' कहा जाता है। उन्होंने जीवन जीने के पांच सिद्धांत दिए थे, जिन्हें 'पंच ककार' (केश, कड़ा, कृपाण, कंघा और कच्छा) कहा जाता है। गुरु गोबिंद सिंह ने ही 'गुरु ग्रंथ साहिब' को सिखों के स्थायी गुरु का दर्जा दिया था। सन् 1708 में गुरु गोबिंद सिंह ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में शिविर लगाया था। वहां जब उन्हें लगा कि अब उनका अंतिम समय आ गया है, तब उन्होंने संगतों को आदेश दिया कि अब गुरु ग्रंथ साहिब ही आपके गुरु हैं। गुरु जी का जीवन दर्शन था कि धर्म का मार्ग ही सत्य का मार्ग है और सत्य की हमेशा जीत होती है। वे कहा करते थे कि मनुष्य का मनुष्य से प्रेम ही ईश्वर की भक्ति है, अतः जरूरतमंदों की मदद करो। अपने उपदेशों में उनका कहना था कि ईश्वर ने मनुष्यों को इसलिए जन्म दिया है ताकि वे संसार में अच्छे कर्म करें और बुराई से दूर रहें। उन्होंने कई बार मुगलों को परास्त किया। आनंदपुर साहिब में तो मुगलों से उनके संघर्ष और उनकी वीरता का स्वर्णिम इतिहास बिखरा पड़ा है। सन् 1700 में दस हजार से भी ज्यादा मुगल सैनिकों को सिख जांबाजों के सामने मैदान छोड़कर भागना पड़ा था और गुरु जी की सेना ने 1704 में मुगलों के अलावा उनका साथ दे रहे पहाड़ी हिन्दू शासकों को भी करारी शिकस्त दी थी। मुगल शासक औरंगजेब की भारी-भरकम सेना को भी आनंदपुर साहिब में दो-दो बार धूल चाटनी पड़ी थी। गुरु गोबिंद सिंह के चारों पुत्र अजीत सिंह, फतेह सिंह, जोरावर सिंह और जुझार सिंह भी उन्हीं की भांति बेहद निडर और बहादुर योद्धा थे। अपने धर्म की रक्षा के लिए मुगलों से लड़ते हुए गुरु गोबिंद सिंह ने अपने पूरे परिवार का बलिदान कर दिया था। उनके दो पुत्रों बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह ने चमकौर के युद्ध में शहादत प्राप्त की थी। 26 दिसम्बर 1704 को गुरु गोबिंद सिंह के दो अन्य साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने पर सरहिंद के नवाब द्वारा दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था और माता गुजरी को किले की दीवार से गिराकर शहीद कर दिया गया था। गुरु गोबिंद सिंह ने 7 अक्टूबर 1708 को महाराष्ट्र के नांदेड़ में स्थित श्री हुज़ूर साहिब में अपने प्राणों का त्याग किया था।

अभियान

अहंकार से भक्ति तक: बाणासुर और श्रीकृष्ण के महासंग्राम की दिव्य कथा

पुराणों में अनेक कथाएँ ऐसी हैं जो केवल युद्ध या पराक्रम का वर्णन नहीं करतीं, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपे अहंकार, प्रेम, भक्ति और धर्म के गहरे अर्थ को उजागर करती हैं। बाणासुर और भगवान श्रीकृष्ण के बीच हुआ युद्ध भी ऐसी ही एक अद्भुत कथा है, जिसमें शक्ति के घमंड का अंत और करुणा, धर्म तथा प्रेम की विजय का संदेश छिपा हुआ है। यह कथा भागवत पुराण और हरिवंश पुराण में विस्तार से वर्णित है और आज भी श्रद्धालुओं के हृदय को भावविभोर कर देती है। बाणासुर असुरराज महाबली बलि का पुत्र था। बलि अपने दान, त्याग और वचनबद्धता के लिए विख्यात थे, परंतु उनका पुत्र बाणासुर अपनी अपार शक्ति और तपस्या के कारण धीरे-धीरे अहंकार में डूब गया। बाणासुर भगवान शिव का परम भक्त था। उसने वर्षों तक कठोर तप किया, हिमालय की गुफाओं में साधना की, शरीर को कष्ट दिए और मन को एकाग्र कर महादेव को प्रसन्न किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और वरदान माँगने को कहा। बाणासुर ने विनम्र स्वर में यह वर माँगा कि भगवान शिव स्वयं शोणितपुर की रक्षा करें। महादेव ने "तथास्तु" कहकर उसकी इच्छा पूरी कर दी। इस वरदान के बाद बाणासुर का आत्मविश्वास धीरे-धीरे घमंड में बदल गया। उसके पास एक हजार भुजाएँ थीं और वह स्वयं को अजेय समझने लगा। देवता, गंधर्व

और अनेक राजाओं को उसने अपने पराक्रम से परास्त किया। जहाँ भी उसका नाम लिया जाता, वहाँ भय की लहर दौड़ जाती। वह युद्ध के लिए सदैव आतुर रहता और उसे लगने लगा कि संसार में कोई भी ऐसा योद्धा नहीं है जो उसका सामना कर सके। एक बार उसने शिवजी से ही कह दिया कि अब उसके लिए युद्ध करने योग्य कोई शत्रु नहीं बचा है। शिवजी ने मुस्कुराकर इतना ही कहा कि समय आने पर उसका अभिमान स्वयं टूटेगा। उसी शोणितपुर में बाणासुर की एक अत्यंत सुंदरी और सुसंस्कृत पुत्री थी, जिसका नाम उषा था। एक रात उषा ने स्वप्न में एक दिव्य और तेजस्वी युवक को देखा और उसी क्षण उसका हृदय प्रेम से भर गया। जागने के बाद भी उस युवक की छवि उसके मन से नहीं गई। उसने अपनी सखी चित्रलेखा को यह स्वप्न सुनाया। चित्रलेखा योग और मायावी शक्तियों में निपुण थी। उसने ध्यान के माध्यम से उस युवक की पहचान की और जान लिया कि वह द्वारका के राजकुमार अनिरुद्ध हैं, जो भगवान श्रीकृष्ण के पौत्र और प्रद्युम्न के पुत्र थे। चित्रलेखा ने अपनी योगशक्ति से अनिरुद्ध को द्वारका से शोणितपुर पहुँचा दिया। उषा और अनिरुद्ध का मिलन हुआ और दोनों एक-दूसरे के प्रेम में बंध गए। यह प्रेम गुप्त रूप से महल में पनपने लगा, परंतु सत्य अधिक समय तक छिपा नहीं रहता। एक दिन महल के सैनिकों ने अनिरुद्ध को देख लिया और यह समाचार बाणासुर तक पहुँचा। बाणासुर क्रोध से भर उठा। उसने इसे अपने मान-सम्मान पर आघात माना और बिना कुछ सोचे-समझे अनिरुद्ध को नागपाश में बाँधकर कारागार में बंद कर दिया।

द्वारका में जब यह समाचार पहुँचा, तो श्रीकृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न का क्रोध स्वाभाविक था। श्रीकृष्ण ने इसे केवल पारिवारिक अपमान नहीं, बल्कि अधर्म का कार्य माना। उन्होंने विशाल सेना के साथ शोणितपुर की ओर प्रस्थान किया। जब द्वारका की सेना शोणितपुर पहुँची, तो आकाश शंखनाद से गूंज उठा और धरती रणघोष से कांप उठी। बाणासुर भी अपनी पूरी सेना के साथ युद्धभूमि में उतर आया। उसके साथ शिवजी के गण और कार्तिकेय भी थे, क्योंकि शिवजी ने उसे संरक्षण का वरदान दिया था। युद्ध अत्यंत भयानक था। श्रीकृष्ण के सुदर्शन चक्र और बलराम के हल से असुरों की सेना में हाहाकार मच गया। आकाश में अस्त्र-शस्त्रों की वर्षा होने लगी। जब बाणासुर की सेना कमजोर पड़ने लगी, तब स्वयं भगवान शिव रणभूमि में उतरे। यह दृश्य अद्भुत था—एक ओर नारायण, दूसरी ओर महादेव। दोनों के बीच अस्त्रों का आदान-प्रदान हुआ, परंतु यह युद्ध द्वेष से नहीं, बल्कि लीला और धर्म की मर्यादा के लिए था।

अंततः श्रीकृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से बाणासुर की हजारों भुजाएँ काट दीं, केवल चार भुजाएँ शेष छोड़ दीं। पीड़ा और लज्जा से भरा बाणासुर भूमि पर गिर पड़ा। तभी भगवान शिव ने श्रीकृष्ण से उसे जीवित छोड़ने का आग्रह किया। श्रीकृष्ण ने महादेव की बात मान ली और कहा कि अहंकार का अंत हो चुका है, अब बाणासुर जीवित रहेगा, परंतु विनम्रता के साथ। बाणासुर ने शिव और श्रीकृष्ण दोनों के चरणों में गिरकर क्षमा माँगी और अपने अभिमान के लिए पश्चाताप किया। इसके बाद अनिरुद्ध और उषा का विधिवत विवाह हुआ और शोणितपुर में आनंद और उत्सव का वातावरण छा गया। बाणासुर ने अपना राज्य धर्मपूर्वक चलाने का संकल्प लिया। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति यदि अहंकार से जुड़ जाए तो विनाश का कारण बनती है, लेकिन वही शक्ति जब भक्ति और धर्म के साथ जुड़ती है तो कल्याण का मार्ग खोलती है। शिव और विष्णु का यह प्रसंग भी यही बताता है कि दोनों में कोई भेद नहीं, वे एक ही परम सत्य के दो स्वरूप हैं और अंततः धर्म की ही विजय होती है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004 (2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002 and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

एक अंगीठी ने बुझा दिया चार जिंदगियों का उजाला ठंड से बचने की कोशिश बनी मौत की वजह

(जीएनएस)। सारण जिले के छपरा शहर में कड़ाके की ठंड से राहत पाने की कोशिश एक परिवार के लिए ऐसी त्रासदी बन गई, जिसने पूरे इलाके को गहरे शोक में डुबो दिया। भगवान बाजार थाना क्षेत्र की अंबिका कॉलोनी में अंगीठी के धुएं से दम घुटने के कारण एक ही परिवार के चार सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हृदयविदारक हादसे में तीन मासूम बच्चे और उनकी वृद्ध दादी ने अपनी जान गंवा दी, जबकि परिवार के तीन अन्य सदस्य जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं।

स्थानीय लोगों और परिजनों के अनुसार, शुक्रवार की रात ठंड असहनीय होने के कारण परिवार के सभी सदस्य एक ही कमरे में इकट्ठा होकर सोए थे। सर्दी से बचने के लिए कमरे के भीतर अंगीठी जलाई गई थी। ठंड के कारण दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह बंद कर दी गईं, ताकि ठंडी हवा अंदर न आ सके। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही बंद कमरा धीरे-धीरे मौत का जाल बन जाएगा। रात भर अंगीठी से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कमरे में भरती रही और ऑक्सीजन की मात्रा घटती चली गई। सोते हुए सभी लोग जहरीली गैस की चपेट में आ गए।

सुबह जब घर में हलचल नहीं दिखी तो परिवार के एक सदस्य को अनहोनी की आशंका हुई। उसने जब बाकी लोगों को जगाने की कोशिश की और कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे और सभी को तत्काल सदर अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने चार लोगों को मृत घोषित कर दिया। इस खबर ने न केवल परिवार बल्कि पूरे मोहल्ले को झकझोर कर रख दिया।

इस हादसे में जिन लोगों की जान गई, उनमें तीन साल का तेजाश, चार साल का अध्याय, सात महीने की मासूम गुड़िया और उनकी 70 वर्षीय दादी कमलावती देवी शामिल हैं। एक ही घर से उठी चार अर्थियों की कल्पना मात्र से ही लोगों की आंखें नम हो गईं। वहीं अमित कुमार, अमीषा और परिवार के एक अन्य सदस्य की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका इलाज सदर अस्पताल में जारी है। डॉक्टरों के अनुसार, समय पर उपचार मिलने से उनकी जान बचने की उम्मीद है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है।

घटना की सूचना मिलते ही जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सदर अस्पताल पहुंचे। एसएसपी डॉ. कुमार आशीष, एएसपी राम पुकार सिंह समेत भगवान बाजार और टाउन थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि हादसे के पीछे कोई अन्य कारण तो नहीं था।

इस दर्दनाक घटना के बाद प्रशासन और पुलिस ने आम नागरिकों से सतर्कता बरतने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा है कि सर्दी के मौसम में बंद कमरों में अंगीठी, कोयला या किसी भी प्रकार की आग जलाना बेहद खतरनाक हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस बिना गंध के फैलती है और इंसान को इसका एहसास भी नहीं होता। यदि मजबूरी में अंगीठी का उपयोग करना पड़े, तो कमरे में पर्याप्त हवा का आवागमन जरूरी है और दरवाजे-खिड़कियां खुली रखनी चाहिए।

अंबिका कॉलोनी में पसरा सन्नाटा इस बात की गवाही दे रहा है कि ठंड से बचने का एक छोटा सा निर्णय कैसे पूरे परिवार की खुशियां छीन सकता है। यह हादसा न केवल एक परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है, बल्कि समाज के लिए भी एक गंभीर चेतावनी है कि थोड़ी सी लापरवाही कितनी बड़ी कीमत वसूल सकती है।

पाकिस्तान का प्रतिभा-संकट: डॉक्टर इंजीनियर और पेशेवर क्यों छोड़ रहे हैं देश

(जीएनएस)। इस्लामाबाद। पाकिस्तान आज जिस गहरे संकट से गुजर रहा है, उसकी सबसे बड़ी और चिंताजनक तस्वीर देश से हो रहे प्रतिभा पलायन में दिखाई दे रही है। आर्थिक बदहाली, राजनीतिक अस्थिरता, सुरक्षा को लेकर बढ़ती अनिश्चितता और भविष्य की धुंधली तस्वीर ने पाकिस्तान के शिक्षित और कुशल वर्ग को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। हालात यह हैं कि बीते दो वर्षों में हजारों डॉक्टर, इंजीनियर, लेखाकार और अन्य उच्च-स्तरीय पेशेवर पाकिस्तान को अलविदा कह चुके हैं और यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान के आव्रजन और विदेश रोजगार ब्यूरो की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दो वर्षों में लगभग 30 हजार डॉक्टर, इंजीनियर और पेशेवर देश छोड़कर विदेश चले गए हैं। इन आंकड़ों में करीब 5,000 डॉक्टर, 11,000 इंजीनियर और 13,000 से अधिक लेखाकार शामिल हैं। यह पलायन केवल रोज़गार की तलाश तक

सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के भीतर गहराते अविश्वास और टूटते सिस्टम की कहानी भी बयां करता है। सोशल मीडिया पर इन आंकड़ों के सामने आने के बाद लोग व्यंग्य कर रहे हैं कि जहां रोजगार के अवसर सीमित हों, शोध और विकास की संभावनाएं खत्म हो रही हों और व्यक्तिगत सुरक्षा की गारंटी न हो, वहां से प्रतिभाओं का पलायन होना स्वाभाविक है।

स्थिति इसलिए भी अधिक गंभीर मानी जा रही है क्योंकि यह पलायन अब केवल श्रमिक वर्ग या कम वेतन वाली नौकरियों तक सीमित नहीं रहा। रिपोर्ट से साफ है कि पाकिस्तान का उच्च शिक्षित और कुशल वर्ग भी तेजी से देश छोड़ रहा है। इसका सबसे गहरा असर स्वास्थ्य क्षेत्र पर पड़ रहा है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2011 से 2024 के बीच नर्सों के पलायन में 2,144 प्रतिशत की चौंकाने वाली वृद्धि दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यही रुझान 2025 तक जारी रहा, तो पाकिस्तान की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा सकती है और आम जनता को बुनियादी इलाज तक के लिए भारी संकट का सामना करना पड़ेगा। आंकड़े बताते हैं कि हर साल प्रवासन का ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। वर्ष 2024 में लगभग 7.27 लाख पाकिस्तानी नागरिकों ने विदेश में नौकरी के लिए पंजीकरण कराया था, जबकि 2025 में नवंबर तक 6.87 लाख लोग यह प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। इन आंकड़ों को साझा करते हुए पूर्व सीनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने साफ कहा कि जब तक पाकिस्तान में राजनीतिक सुधार नहीं होंगे, तब तक अर्थव्यवस्था में भी सुधार संभव नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि बार-बार इंटरनेट बंद किए जाने के कारण पाकिस्तान को करीब 1.62 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है और 23 लाख से अधिक फ्रीलांस नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं, जिससे युवा वर्ग का मोहभंग और तेज हो गया है। सरकार की ओर से हालात को संभालने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन वे नाकाफी साबित हो रहे हैं। अवैध प्रवासन और आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए हवाई अड्डों पर कड़ी निगरानी बढ़ा दी गई है। वर्ष 2025 में अब तक 66,154 यात्रियों को विदेश यात्रा से रोका जा चुका है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दोगुना है। इसके बावजूद देश छोड़ने की चाह कम नहीं हो रही। खाड़ी देशों समेत अन्य देशों से अवैध प्रवासन और भीख मांगने के आरोप में हजारों पाकिस्तानी नागरिकों को निर्वासित भी किया गया है, लेकिन यह सख्ती भी लोगों के फैसले को बदल नहीं पा रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठान के बयानों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ महीने पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने इस पलायन को 'बौद्धिक पलायन' नहीं बल्कि 'बौद्धिक लाभ' बताया था। हालांकि अब जब इसके गंभीर दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, तो इस बयान की देश और विदेश में तीखी आलोचना हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पाकिस्तान ने जल्द ही राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक सुधार और युवाओं के लिए सुरक्षित व सम्मानजनक भविष्य का भरोसा नहीं दिया, तो यह प्रतिभा पलायन देश को लंबे समय तक अपूरणीय क्षति पहुंचा सकता है। यह संकट अब केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान के भविष्य पर एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया है।

गिर के बागानों में संकट: इस साल देरी से बाजार में आ सकता है विश्व प्रसिद्ध केसरिया आम, किसान और उपभोक्ता दोनों चिंतित

(जीएनएस)। गुजरात के गिर क्षेत्र से आम प्रेमियों के लिए इस बार चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आ रही है। विश्व प्रसिद्ध केसरिया आम, जिसे "आमों का राजा" कहा जाता है, उसकी उपलब्धता इस साल तय समय से काफी देर से होने की आशंका जताई जा रही है। गिर के बागानों में केसरिया आम की खेती करने वाले किसान इस समय गंभीर संकट से गुजर रहे हैं। लगातार दोहरी फसल लेने की मजबूरी, बेमौसम बारिश, मौसम की अनिश्चितता और कीटों के बढ़ते हमलों ने आम की फसल को गहरा नुकसान पहुंचाया है। आमतौर पर दिसंबर के महीने में गिर क्षेत्र के बागानों में केसरिया आम के पेड़ों पर बौर आना शुरू हो जाता है और हरियाली के बीच सुनहरे रंग की झलक दिखाई देने लगती है, लेकिन इस साल हालात बिल्कुल अलग हैं। किसानों के अनुसार अभी तक केवल 10 से 15 प्रतिशत पेड़ों पर ही बौर नजर आया है, जबकि शेष बागान लगभग सूने पड़े हैं। कीटनाशकों के लगातार छिड़काव के बावजूद इल्ली और अन्य कीटों का प्रकोप थम नहीं रहा, जिससे पेड़ों की सेहत

लगातार कमजोर हो रही है और फल बनने की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। दोहरी फसल के कारण पेड़ों की प्राकृतिक ताकत पहले ही कम हो चुकी थी, ऊपर से मौसम की मार ने स्थिति और खराब कर दी है। सर्दियों में ठंड का असामान्य व्यवहार और अचानक हुई नमी ने बागानों को बड़ा झटका दिया है, जिसके चलते 70 से 80 प्रतिशत तक बागान अभी तक खाली पड़े बताए जा रहे हैं। गिर क्षेत्र में लगभग 15 से 16 हजार हेक्टेयर भूमि पर केसरिया आम की खेती होती है, जो न केवल गुजरात बल्कि पूरे देश और विदेशों में अपनी खुशबू, मिठास और रंग के लिए मशहूर है। यदि आने वाले हफ्तों में मौसम अनुकूल नहीं हुआ और कीटों पर नियंत्रण नहीं पाया गया, तो फसल को और अधिक नुकसान होने की आशंका है। ऐसी स्थिति में केसरिया आम के बाजार में आने में देरी तो होगी ही, साथ ही इसकी कीमतें भी आसमान छू सकती हैं, जिसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। कृषि वैज्ञानिक किसानों से लगातार अपील कर रहे हैं कि बागानों की नियमित निगरानी करें और इल्ली या अन्य कीट दिखाई देते ही तुरंत उचित दवाओं का छिड़काव करें, ताकि बची-खुची फसल को सुरक्षित रखा जा सके। यह संकट केवल किसानों की आमदनी तक सीमित नहीं है, बल्कि पारंपरिक खेती पर बदलते मौसम के बढ़ते खतरे को भी उजागर करता है। गिर के किसान अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आने वाले दिनों में मौसम स्थिर होगा और केसरिया आम की यह अनमोल फसल पूरी तरह बर्बाद होने से बच जाएगी, ताकि देश और दुनिया के आम प्रेमी एक बार फिर इस खास स्वाद का आनंद ले सकें।

नेपाल के राजदूत डॉ. शंकर प्रसाद शर्मा ने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल से शिष्टाचार भेंट की

- टूरिज्म, इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हाइड्रो एनर्जी एवं मैन्युफैक्चरिंग तथा एजुकेशन सेक्टर में सहभागिता पर परामर्श
- प्रधानमंत्री के दिशादर्शन में गुजरात द्वारा बहुविध क्षेत्रों में किए गए विकास से प्रभावित हुए नेपाल के राजदूत

(जीएनएस)। गांधीनगर : भारत में नेपाल के राजदूत डॉ. शंकर प्रसाद शर्मा ने शनिवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल से शिष्टाचार भेंट की।

डॉ. शर्मा नेपाल के टूरिज्म प्रवोशन के लिए गुजरात की यात्रा पर आए हैं। aइस बीच उन्होंने मुख्यमंत्री से यह शिष्टाचार भेंट-बैठक आयोजित की।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दिशादर्शन में गुजरात द्वारा टूरिज्म सेक्टर में जो विश्व आकर्षण स्थापित किए हैं, उसकी डॉ. शर्मा ने प्रशंसा की। उन्होंने विशेष रूप से टूरिज्म, इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हाइड्रो एनर्जी एवं मैन्युफैक्चरिंग तथा एजुकेशन सेक्टर में सहभागिता पर मुख्यमंत्री के साथ परामर्श किया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में गुजरात के मैन्युफैक्चरिंग हब बने होने तथा सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जैसे इमर्जिंग सेक्टर्स

में भी अग्रणी बनने को सज्ज हुए होने का विवरण दिया।

इसके अलावा; मुख्यमंत्री ने नेपाल के राजदूत के समक्ष भूमिका दी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिट, सफेद रण जैसे पर्यटन स्थलों और सोमनाथ, द्वारका तथा अंबाजी जैसे आध्यात्मिक पर्यटन स्थलों के साथ गुजरात विश्वभर के पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बना है।

नेपाल के राजदूत डॉ. शंकर प्रसाद शर्मा तथा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के बीच इस शिष्टाचार भेंट-बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार, उद्योग विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती ममता वर्मा, उद्योग आयुक्त श्री पी. स्वरूप तथा नेपाली प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी सहभागी हुए।

भारतीय रेलवे की अगले 5 वर्षों में प्रमुख शहरों में रेल गाड़ियों की संचालन क्षमता दोगुनी करने की योजना

प्रमुख शहरों में कोचिंग टर्मिनलों का विस्तार यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने, भीड़भाड़ कम करने और राष्ट्रव्यापी संपर्क सुविधा में सुधार लाने के लिए किया जाएगा: रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव

(जीएनएस)। यात्रा की मांग में लगातार हो रही तीव्र वृद्धि को देखते हुए, अगले 5 वर्षों में प्रमुख शहरों की नई रेल गाड़ियों के संचालन की क्षमता को वर्तमान स्तर से दोगुना करना आवश्यक है। आगामी वर्षों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्तमान बुनियादी ढांचे को मजबूत करना होगा। वर्ष 2030 तक संचालन क्षमता को दोगुना करने के लिए निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे:

i. मौजूदा टर्मिनलों को अतिरिक्त प्लेटफॉर्म, स्टेबलिंग लाइन, पिट लाइन और पर्याप्त शंटिंग सुविधाओं से सुसज्जित करना।

ii. शहरी क्षेत्र में और उसके आसपास नए टर्मिनलों की पहचान और निर्माण करना।

iii. मेगा कोचिंग कॉम्प्लेक्स सहित रखरखाव सुविधाएं।

iv. विभिन्न स्थानों पर रेल गाड़ियों की

बढ़ती संख्या की व्यवस्था करने के लिए यातायात सुविधा कार्यों, सिग्नलिंग उन्नयन और मल्टीट्रैकिंग के माध्यम से अनुभागीय क्षमता में वृद्धि करना।

देश के 48 प्रमुख शहरों की एक व्यापक योजना विचाराधीन है। इस योजना में निर्धारित समय सीमा के भीतर रेल गाड़ियों की संचालन क्षमता को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नियोजित, प्रस्तावित या पहले से स्वीकृत कार्यों को शामिल किया जाएगा।

क्षमता को वर्ष 2030 तक दोगुना करने की योजना है, लेकिन यह आशा है कि अगले 5 वर्षों में क्षमता में क्रमिक वृद्धि की जाएगी ताकि क्षमता वृद्धि के लाभ तुरंत प्राप्त किए जा सकें। इससे आने वाले वर्षों में यातायात की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने में सहायता मिलेगी। योजना में कार्यों को तीन श्रेणियों, अर्थात् तत्काल, अल्पकालिक और दीर्घकालिक में वर्गीकृत किया जाएगा।

केंद्रीय रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "हम यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने और भीड़भाड़ को कम करने के लिए विभिन्न शहरों में कोचिंग टर्मिनलों का विस्तार कर रहे हैं और अनुभागीय एवं परिचालन क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं। इस कदम से हमारे रेलवे नेटवर्क का उन्नयन होगा और राष्ट्रव्यापी संपर्क सुविधा में सुधार होगा।"

अहमदाबाद क्षेत्र से 150 से अधिक ट्रेनों का संचालन होगा संभव,अहमदाबाद स्टेशन पर ट्रेनों का लोड कम होगा, संचालन होगा और भी सुगम

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के वटवा में लगभग 3 किमी का एक मेगा कोचिंग टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा, जिसके माध्यम से अहमदाबाद स्टेशन पर ट्रेनों का अत्यधिक लोड काफी हद तक कम होगा और पूरे क्षेत्र में ट्रेन संचालन क्षमता में बड़ी वृद्धि होगी। यह परियोजना मंडल की 2.5 गुना ट्रेन हैंडलिंग क्षमता बढ़ाने की योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।

वटवा टर्मिनल की मुख्य संरचना और आधुनिक सुविधाएँ

- वटवा का यह मेगा टर्मिनल लगभग 3 किमी लंबा होगा, जिसकी चौड़ाई LC-305 पर 76 मीटर, ROB-713 (SP रिंग रोड) पर 300 मीटर तथा खारी ब्रिज नं. 711 पर 118 मीटर रहेगी।
- टर्मिनल में कुल 12 पिट लाइनें बनाई जा रही हैं, जिनसे ट्रेनों का गहन व नियमित मेंटेनेंस आसानी से संभव होगा।
- 29 स्टेबलिंग लाइनें उपलब्ध कराई जाएँगी, जिनमें खाली रेक सुरक्षित खड़े किए जा सकेंगे।
- 2 वॉशिंग लाइनें बनाई जाएँगी, जिनसे रेक की तेज़ और निरंतर सफाई सुनिश्चित की जा सकेगी।
- 2 सिक लाइनें (600 मीटर) बनाई जा रही हैं, जहाँ खराब कोचों की मरम्मत और तकनीकी सुधार किए जा सकेंगे।
- 6 नए अतिरिक्त प्लेटफॉर्म बनाए जाएँगे, जिससे प्लेटफॉर्मों की कुल संख्या 9 हो जाएगी और ट्रेनों का आरंभ व समाप्ति अधिक सुव्यवस्थित होगी।
- वटवा टर्मिनल के पूर्ण संचालन के बाद प्रतिदिन 36 जोड़ी ट्रेनों का प्राइमरी मेंटेनेंस, 15 ट्रेनों की प्लेटफॉर्म रिटर्न सुविधा और कुल 51 ट्रेनों का संचालन संभव होगा।
- अकेले वटवा टर्मिनल ही मंडल की कुल क्षमता वृद्धि में लगभग 85% योगदान देगा।

अहमदाबाद मंडल में व्यापक क्षमता वृद्धि–सभी स्टेशनों पर तेजी से चल रहा विकास

- वटवा के साथ-साथ अहमदाबाद, साबरमती, असारवा और गांधी नगर कैपिटल स्टेशनों पर भी बड़े पैमाने पर अपग्रेडेशन कार्य जारी हैं, जो पूरे नेटवर्क को मजबूत बनाएँगे।
- सभी कार्य पूर्ण होने पर मंडल की ट्रेन ओरिजिनेशन क्षमता औसत 58 से बढ़कर 150 प्रतिदिन हो जाएगी, जो अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि होगी।
- अहमदाबाद स्टेशन पर ट्रेन संचालन क्षमता 38 ट्रेनों से बढ़कर 45–50 ट्रेनों प्रतिदिन तक पहुँच जाएगी।
- साबरमती स्टेशन पर यह क्षमता 20 से बढ़कर 27–28 ट्रेन प्रतिदिन होगी।
- असारवा स्टेशन पर क्षमता 6 से बढ़कर 11–12 ट्रेन प्रतिदिन तक बढ़ेगी।
- गांधीनगर कैपिटल स्टेशन की क्षमता 6 से बढ़कर 8–10 ट्रेन प्रतिदिन तक पहुँच जाएगी।
- वटवा स्टेशन की संचालन क्षमता सबसे अधिक वृद्धि के साथ 6 से बढ़कर 56–57 ट्रेन प्रतिदिन तक पहुँचेगी।

यात्रियों को बड़े लाभ और रणनीतिक नेटवर्क सुधार

- क्षमता वृद्धि से यात्रियों को प्रतिदिन की यात्री वहन क्षमता 1,02,000 से बढ़कर 2,62,000 प्रतिदिन (लगभग 2.5 गुना) तक का लाभ मिलेगा।
- अधिक संख्या में एक्सप्रेस, MEMU, फेस्टिवल स्पेशल और लंबी दूरी की ट्रेन सेवाओं की शुरुआत संभव होगी।
- पिट लाइन बनने से 23-कोच LHB रेक, वंदेभारत एवं अमृत भारत जैसी ट्रेनों का मेंटेनेंस संभव होगा जिससे ट्रेनों की उपलब्धता बढ़ेगी।
- अहमदाबाद और साबरमती यार्ड में भीड़ कम होने से ट्रेनों की समयपालनता में वृद्धि होगी।
- अहमदाबाद यार्ड रीमॉडलिंग, साबरमती में नई पिट लाइन व प्लेटफॉर्म निर्माण, असारवा–साबरमती Y-कनेक्शन तथा गांधीग्राम–साबरमती–खोड़ियारY-कनेक्शन जैसे प्रमुख नेटवर्क सुधार कार्य ट्रेन मूवमेंट को तेज़, सुरक्षित और निर्बाध बनाएँगे।

इन सभी परियोजनाओं के पूरा होने पर अहमदाबाद मंडल पश्चिम रेलवे का सबसे सक्षम, आधुनिक और भविष्य-उन्मुख टर्मिनल क्लस्टर बनकर उभरेगा, जो प्रतिदिन 150 ट्रेनों का संचालन दक्षता से कर सकेगा। यह यात्रियों की सुविधा और सेवा गुणवत्ता में ऐतिहासिक सुधार लाएगा। साथ ही अहमदाबाद मण्डल पर कई स्टेशनों पुनर्विकास का कार्य चल रहा है जिससे स्टेशनों की संचालन क्षमता बढ़ेगी।

- अहमदाबाद स्टेशन का पुनर्विकास तीव्र गति से चल रहा है। स्टेशन बिल्डिंग की साउथ विंग का कार्य जून-जुलाई 2026 तक पूर्ण होने की संभावना है।
- साबरमती स्टेशन का पुनर्विकास भी तेजी से चल रहा है। इसका कार्य भी नववर्ष 2026 में पूर्ण हो जाएगा।
- न्यू भुज रेलवे स्टेशन का उन्नयन कार्य तेज़ी से प्रगति पर है। इस परियोजना की स्वीकृत लागत लगभग 200 करोड़ है, इसका 75% से अधिक कार्य अब तक पूर्ण हो चुका है। अप्रैल 2026 तक पूर्ण होने की संभावना है।
- अहमदाबाद मण्डल पर अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत आसारवा, मणिनगर, चांदलोडिया, वटवा, कलोल, सामाख्याली, धांगध्रा, भचाऊ, गांधीधाम, सिद्धपुर, उंझा, महेसाणा, पालनपुर, पाटन, हिम्मतनगर और भीलड़ी स्टेशनों का पुनर्विकास का कार्य तेजी से चल रहा है।

भावनगर मंडल से होकर चलने वाली 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे विस्तारित

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु भावनगर मंडल से होकर चलने वाली 4 जोड़ी "स्पेशल ट्रेनों" के फेरे विस्तारित किए गए हैं। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. ट्रेन संख्या 09208/09207 भावनगर-बान्द्रा-भावनगर साप्ताहिक स्पेशल

ट्रेन संख्या 09207 बांद्रा टर्मिनस-भावनगर स्पेशल, जिसे पहले 26 दिसंबर, 2025 तक अधिसूचित किया गया था, अब उसे 27 फरवरी, 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09208 भावनगर-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल, जिसे पहले 25 दिसंबर, 2025 तक अधिसूचित किया गया था, अब उसे 27 फरवरी, 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

2. ट्रेन संख्या 09212/09211 बोटाद-गांधीग्राम-बोटाद दैनिक स्पेशल (अनारक्षित)

ट्रेन संख्या 09211 गांधीग्राम-बोटाद स्पेशल जिसे पहले 31 दिसंबर, 2025 तक अधिसूचित किया गया था, अब उसे 28 फरवरी, 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इसी तरह, ट्रेन संख्या 09212 बोटाद-गांधीग्राम स्पेशल जिसे पहले 31 दिसंबर, 2025 तक अधिसूचित किया गया था, अब उसे 28 फरवरी, 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इसी तरह, ट्रेन संख्या 09530 भावनगर-धोला स्पेशल जिसे पहले 31 दिसंबर, 2025 तक अधिसूचित किया गया था, अब उसे 28 फरवरी, 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

3. ट्रेन संख्या 09215/09216 गांधीग्राम-भावनगर-गांधीग्राम दैनिक स्पेशल (अनारक्षित)

ट्रेन संख्या 09216 भावनगर-गांधीग्राम स्पेशल जिसे पहले 31 दिसंबर, 2025 तक अधिसूचित किया गया था, अब उसे 28 फरवरी, 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इसी तरह, ट्रेन संख्या 09215 गांधीग्राम-भावनगर स्पेशल जिसे पहले 31 दिसंबर, 2025 तक अधिसूचित किया गया था, अब उसे 28 फरवरी, 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

4.ट्रेन संख्या 09529/09530 धोला-भावनगर-धोला दैनिक स्पेशल (अनारक्षित)

ट्रेन संख्या 09529 धोला-भावनगर स्पेशल जिसे पहले 31 दिसंबर, 2025 तक अधिसूचित किया गया था, अब उसे 28 फरवरी, 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इसी तरह, ट्रेन संख्या 09530 भावनगर-धोला स्पेशल जिसे पहले 31 दिसंबर, 2025 तक अधिसूचित किया गया था, अब उसे 28 फरवरी, 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

गौरतलब है कि धोला-भावनगर-धोला दैनिक स्पेशल ट्रेन भावनगर टर्मिनस स्टेशन पर पीट लाइन की मरम्मत हेतु चल रहे कार्य की वजह से 25 जनवरी, 2026 तक के लिए निरस्त की गई है, इस कारण से यह ट्रेन कार्य पूर्ण होने के पश्चात 26 जनवरी से 28 फरवरी, 2026 तक के लिए विस्तारित की गई है।

आलू के ढेर पर बैठा किसान मिट्टी के मोल बिक रही मेहनत

(जीएनएस)। फर्रुखाबाद जिले में आलू की बंपर पैदावार इस साल किसानों के लिए वरदान नहीं, बल्कि अभिशाप बनकर सामने आई है। वर्ष 2025 विदा होते-होते किसानों के हिस्से में मुनाफा नहीं, बल्कि कर्ज, चिंता और टूटती उम्मीदें छोड़ गया है। मंडियों में आलू के दाम इस कदर गिर चुके हैं कि किसान अपनी लागत तक निकाल पाने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। हालात यह हैं कि आलू 3.5 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है, जो खेती की लागत से काफी कम है। खेतों में सोना उगाने वाले किसान आज उसी फसल को बेचने के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। शनिवार को फर्रुखाबाद की सातनपुर आलू मंडी में आलू का न्यूनतम भाव 351 रुपये और अधिकतम 501 रुपये प्रति कुंतल दर्ज किया गया। यह दरें किसानों की उम्मीदों और मेहनत पर सीधा प्रहार करती

दिखीं। मंडी में एक दिन में 150 से अधिक ट्रकों की आवक ने हालात और बिगाड़ दिए। मांग कमजोर रही, जबकि आपूर्ति लगातार बढ़ती चली गई। परिणामस्वरूप, भाव में गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। किसानों के चेहरों पर मायूसी साफ झलक रही है और आढ़ती भी इस हालात में खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।

आलू आढ़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष सुधीर कुमार वर्मा उर्फ रिंकू वर्मा बताते हैं कि जब आलू के दाम अच्छे होते हैं तो किसान के साथ-साथ आढ़ती वर्ग को भी राहत मिलती है, लेकिन मौजूदा हालात में दोनों ही वर्ग नुकसान झेल रहे हैं। किसानों पर पहले से मौजूद कर्ज का बोझ और बढ़ गया है, वहीं आढ़तियों की आमदनी भी लगातार घटती जा रही है। मंडी में सन्नाटा और चेहरों पर चिंता इस संकट की गंभीरता को बयान कर रही है।

जिले के बड़े आलू उत्पादक सुधांशु गंगवार का कहना है कि इस साल आलू की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। मौसम अनुकूल रहा और उत्पादन उम्मीद से कहीं ज्यादा हुआ, लेकिन यही बंपर पैदावार किसानों की सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। मंडियों में आलू की भरमार हो गई, जिससे भाव रोज नीचे गिरते चले गए। उन्होंने बताया कि आलू की खेती से ही बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और पारिवारिक जिम्मेदारियां चलती हैं, लेकिन जब फसल लागत से भी कम दाम पर बिके, तो भविष्य अंधकारमय नजर आने लगता है। कई परिवारों में बच्चों की पढ़ाई, इलाज और शादी-ब्याह जैसी जरूरतें अधर में लटक गई हैं। घने कोहरे और शीतलहर ने भी हालात को और बिगाड़ दिया है। किसानों का कहना है कि मौसम की मार के चलते उन्हें आलू जल्दी मंडी में उतारना पड़ा, जिससे आवक अचानक बढ़ गई। मजबूरी में की गई यह बिक्री भाव को और नीचे ले गई। ठंड और कोहरे के बीच खेत से मंडी तक पहुंचे आलू के साथ किसानों की उम्मीदें भी ठिठुरती नजर आईं। जिला आलू विकास अधिकारी राघवेंद्र सिंह के अनुसार, फर्रुखाबाद में आलू की खेती केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा से भी जुड़ी हुई है। यहां किसान की पहचान और मान-सम्मान उसकी आलू की खेती से जुड़ा होता है। शादी-ब्याह जैसे सामाजिक फैसलों में भी आलू के रकबे और उत्पादन को देखा जाता है। यही वजह है कि घाटे के बावजूद किसान हर साल आलू की खेती का दायरा बढ़ाते जा रहे हैं। इसका नतीजा यह होता है कि उत्पादन बढ़ता है और बाजार में दाम गिरते चले जाते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस चक्र को तोड़ना है तो किसानों को फसल विविधीकरण की ओर गंभीरता से बढ़ना होगा। केवल आलू पर निर्भर रहना अब घाटे का सौदा बनता जा रहा है।

केजीएमयू में धर्मांतरण और यौन शोषण का गंभीर आरोप, जांच के घेरे में पूरा तंत्र

(जीएनएस)। लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से जुड़ा एक मामला इन दिनों पूरे प्रदेश में चर्चा और चिंता का विषय बना हुआ है। एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर द्वारा लगाए गए यौन शोषण और धर्मांतरण के दबाव के आरोपों ने न सिर्फ चिकित्सा जगत को झकझोर दिया है, बल्कि विश्वविद्यालय प्रशासन, पुलिस और सामाजिक संगठनों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस प्रकरण में फरार आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन मलिक की तलाश जहां पुलिस लगातार कर रही है, वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले की आंतरिक जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने आरोप लगाया है कि उसके साथ लंबे समय तक मानसिक और शारीरिक शोषण किया गया और उस पर शादी से पहले धर्म बदलने का दबाव बनाया गया। यह मामला तब सामने आया जब पीड़िता ने 17 दिसंबर को नशीली गोलियां खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। गंभीर हालत में उसे केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां होश में आने के बाद उसने अपने साथ हुई आपबीती डॉक्टरों और प्रशासन के सामने रखी। इस खुलासे के बाद विश्वविद्यालय परिसर में हड़कंप मच गया।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए केजीएमयू प्रशासन ने पहले विशाखा कमेटी से जांच कराई। कमेटी की रिपोर्ट में आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर को दोषी पाया गया, जिसके आधार पर उसे तत्काल निलंबित कर दिया गया और विश्वविद्यालय परिसर तथा हॉस्टल में उसके प्रवेश पर रोक लगा दी गई। इसके साथ ही यह आशंका भी जताई गई कि आरोपी को फरार होने में किसी न किसी स्तर पर सहयोग मिला हो सकता है। इसी बिंदु को केंद्र में रखते हुए अब प्रशासन ने डॉ. के.के. सिंह के नेतृत्व में पांच सदस्यीय समिति गठित की है, जो यह जांच करेगी कि आरोपी को किसने और कैसे मदद पहुंचाई।

विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि यह मामला केवल व्यक्तिगत अपराध तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे संस्थान की गरिमा, छात्राओं की सुरक्षा और नैतिक जिम्मेदारियों का प्रश्न जुड़ा है। इसलिए जांच निष्पक्ष और गहन होगी तथा दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि पीड़िता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसे सुरक्षित हॉस्टल आवंटित किया गया है और 24 घंटे महिला सुरक्षा गार्ड की तैनाती की गई है, ताकि वह स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सके।

इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग भी सख्त रुख अपनाए हुए है। आयोग की अध्यक्ष बबिता चौहान ने साफ शब्दों में कहा है कि यौन शोषण और धर्मांतरण के दबाव जैसे मामलों में किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। आयोग लगातार प्रकरण की निगरानी कर रहा है और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। दूसरी ओर, इस जांच समिति को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है। नेशनल मेडिकोज ऑर्गनाइजेशन ने समिति की संरचना पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जब मामला महिला से जुड़ा है और इतना संवेदनशील है, तो समिति में किसी महिला सदस्य का न होना गंभीर लापरवाही और असंवेदनशीलता को दर्शाता है। संगठन ने इस पूरे मामले की जांच उत्तर प्रदेश एटीएस या एसटीएफ जैसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की है, ताकि किसी भी प्रकार की लीपापोती की गुंजाइश न रहे।

केजीएमयू से जुड़ा यह प्रकरण अब केवल एक विश्वविद्यालय की आंतरिक समस्या नहीं रह गया है, बल्कि यह सवाल बन गया है कि देश के शीर्ष चिकित्सा संस्थानों में काम करने वाली महिला डॉक्टर कितनी सुरक्षित हैं और जब आरोप संस्थान के भीतर से ही उठते हैं, तो निष्पक्ष जांच कैसे सुनिश्चित की जाए।

सुरेंद्रनगर भूमि घोटाले में शिकंजा कसता ईडी बिचौलियों से अफसरों तक बढ़ेगी पूछताछ

(जीएनएस)। सुरेंद्रनगर में सामने आए राष्ट्रीय सहायता से जुड़े भूमि घोटाले ने अब एक नया और गंभीर मोड़ ले लिया है। जांच एजेंसियों की गतिविधियां तेज हो गई हैं और प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में बड़े स्तर पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के अनुसार, आने वाले दिनों में ईडी इस घोटाले से जुड़े कई अहम लोगों को तलब कर सकती है, जिनमें भूमि सौदों के बिचौलिए, दस्तावेजी प्रक्रिया में शामिल व्यक्ति और कुछ सरकारी कर्मचारी शामिल बताए जा रहे हैं। इस कार्रवाई से जिले के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि प्रारंभिक शिकायत के बाद ईडी ने इस मामले में एक और शिकायत दर्ज की थी, जिसके आधार पर अब जांच के दायरे को और व्यापक किया जा रहा है। एसीबी में पहले से दर्ज मामले के साथ-साथ ईडी में दर्ज शिकायत को भी आधार बनाकर अलग स्तर पर जांच शुरू किए जाने की संभावना है। जांच एजेंसियों का मानना है कि इस पूरे प्रकरण में केवल स्थानीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि संगठित तरीके से नियमों को ताक पर रखकर बड़े पैमाने पर वित्तीय लाभ कमाया गया है।

सूत्रों की मानें तो इस घोटाले में डिप्टी मामलतदार चंद्रसिंह मोरी सहित कुछ अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। जमीन के गैर-कृषि (एनए) दर्जे से जुड़े मामलों में नियमों की अनदेखी, संदिग्ध दस्तावेज और संदिग्ध अनुमतियों की कड़ियां अब जांच एजेंसियों के हाथ लगी हैं। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर ईडी अब यह जानने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से जमीनों के पंजीकरण, नामांतरण और उपयोग में बदलाव की प्रक्रिया को प्रभावित किया गया।

इस पूरे मामले में यह भी सामने आ रहा है कि जमीन सौदों के दौरान हुए वित्तीय लेन-देन सामान्य नहीं थे। बैंक खातों, नकद लेन-देन और संदिग्ध भुगतान की परतें अब धीरे-धीरे खुल रही हैं। ईडी की टीम इन लेन-देन का बारीकी से विश्लेषण कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि घोटाले से जुड़े पैसों की अंतिम मंजिल कौन-कौन लोग हैं और किस स्तर तक यह नेटवर्क फैला हुआ है।

सुरेंद्रनगर में सामने आए इस भूमि और एनए घोटाले में करोड़ों रुपये के लेन-देन का संदेह जताया जा रहा है। यही वजह है कि ईडी की सक्रियता को बेहद अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, वैसे-वैसे कई नए नाम और तथ्य सामने आ सकते हैं। इस कार्रवाई ने न सिर्फ प्रशासनिक महकमे को कटघरे में खड़ा कर दिया है, बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी इसकी गूंज सुनाई देने लगी है।

जिले में यह चर्चा आम है कि अगर जांच निष्पक्ष और गहराई से की गई, तो आने वाले दिनों में यह मामला और भी बड़े खुलासों की ओर बढ़ सकता है। फिलहाल ईडी की तैयारी और संभावित समन ने यह साफ कर दिया है कि सुरेंद्रनगर भूमि घोटाले में जांच अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि जिम्मेदार लोगों तक पहुंचने की दिशा में निर्णायक कदम उठाए जाने वाले हैं।

अलाव की चिंगारी से उठा कत्ल का धुआं, कानपुर में साथी की गोली से सुरक्षा कर्मी की मौत

(जीएनएस)। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले में एक मामूली विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया, जब एक सुरक्षा कर्मी ने अपने ही साथी की गोली मारकर हत्या कर दी। यह सनसनीखेज घटना बिल्हौर थाना क्षेत्र के गदरपुर आहार गांव में निर्माणाधीन महर्षि योगी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में सामने आई, जहां तैनात सुरक्षाकर्मी रोजमर्रा की ड्यूटी के दौरान अलाव ताप रहे थे। ठंड की रात में अलाव में लकड़ी रखने को लेकर शुरू हुई कहासुनी इतनी बढ़ गई कि कुछ ही पलों में एक व्यक्ति की जान चली गई और पूरा इलाका दहशत में आ गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, देर रात सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात गार्ड आपस में अलाव के पास बैठे थे। इसी दौरान लकड़ी डालने की बात को लेकर दो सुरक्षाकर्मियों के बीच

बहस शुरू हुई। पहले यह विवाद सिर्फ तीखी नोकझोंक तक सीमित रहा, लेकिन देखते ही देखते दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। माहौल तनावपूर्ण हो गया और अन्य कर्मी बीच-बचाव करने की कोशिश करने लगे, लेकिन गुस्से में तमतमाए आरोपी सुरक्षा गार्ड अनिरुद्ध द्विवेदी ने अचानक अपनी लाइसेंसी दो नाली बंदूक निकाल ली।

आरोप है कि अनिरुद्ध द्विवेदी ने बेहद नजदीक से अपने साथी सुरक्षा गार्ड निर्मल सिंह चंदेल उर्फ नीरज के सीने में गोली मार दी। गोली की आवाज से परिसर में अफरा-तफरी मच गई। निर्मल सिंह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े और मौके पर मौजूद अन्य सुरक्षाकर्मी सहम गए। कुछ लोगों ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वह अंधेरे और आसपास के जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल निर्मल सिंह को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक निर्मल सिंह चंदेल उर्फ नीरज की उम्र करीब 45 वर्ष बताई जा रही है। वह औरंगपुर सांभी गांव का निवासी था और खेती-किसानी के साथ-साथ सुरक्षा गार्ड की नौकरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। उसकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। बिल्हौर थाना पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।

भरूच में कानून पर भारी लापरवाही: शक्तिनाथ हिट एंड रन मामले में अब तक ट्रक चालक पर कार्रवाई नहीं, जनता में आक्रोश

(जीएनएस)। भरूच शहर के शक्तिनाथ क्षेत्र में गुरुवार दोपहर हुई हिट एंड रन की गंभीर घटना ने प्रशासनिक संवेदनशीलता और पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तेज रफ्तार और लापरवाही से चल रहे एक ट्रक ने सड़क पर जा रहे मोपेड सवार को टक्कर मार दी, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी जोरदार थी कि मोपेड सवार दूर जा गिरा। गनीमत रही कि इस हादसे में उसकी जान बच गई, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि दुर्घटना के बाद ट्रक चालक न तो रुका, न ही घायल की मदद की, बल्कि मौके से फरार हो गया। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ट्रक चालक टक्कर मारने के बाद बिना किसी हिचक के तेजी से वहां से निकल जाता है।

इसके बावजूद, 27 दिसंबर की सुबह तक भरूच ए डिवीजन पुलिस स्टेशन में इस मामले में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। पुलिस की इस निष्क्रियता को लेकर स्थानीय लोगों और व्यापारियों में भारी नाराजगी है।

स्थानीय व्यापारी दिलीपसिंह खंडेल ने बताया कि शक्तिनाथ और गोदी रोड इलाके में भारी वाहनों की आवाजाही लगातार बढ़ती जा रही है। आरसीसी सड़क निर्माण के नाम पर भारी ट्रकों को शहर के भीतर से गुजरने की अनुमति दी गई है, जिसका दुरुपयोग खुलेआम हो रहा है। कई ट्रक चालक तेज रफ्तार में वाहन चलाते हैं, न तो ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं और न ही आम नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। इस दुर्घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि प्रशासन की ढील का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी इस इलाके में कई बार लापरवाह ड्राइविंग के कारण दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न होने से ट्रक चालकों के हौसले और बढ़ गए हैं। लोगों को डर है कि यदि समय रहते प्रशासन ने सख्त कदम नहीं उठाए, तो किसी दिन यह लापरवाही किसी की जान ले सकती है।

घटना के बाद क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फरार ट्रक चालक की तत्काल पहचान कर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही, शहर के भीतर भारी वाहनों की आवाजाही पर नियंत्रण लगाने और ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू करने की भी मांग उठ रही है। यह मामला अब केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही और आम नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा सवाल बन चुका है।

नए साल की दस्तक के साथ महंगी हुई कारें, जनवरी से बढ़ेंगी रेनो-निसान समेत कई कंपनियों की कीमतें

(जीएनएस)। नए साल की शुरुआत वाहन खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए महंगाई का संदेश लेकर आ रही है। जनवरी 2026 से देश की कई प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियां अपनी कारों की कीमतों में इजाफा करने जा रही हैं, जिससे आम ग्राहकों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ना तय माना जा रहा है। फ्रांस की दिग्गज कार निर्माता रेनो की भारतीय इकाई रेनो इंडिया ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि 1 जनवरी 2026 से उसकी सभी कारों के दाम बढ़ाए जाएंगे। यह बढ़ोतरी अधिकतम दो प्रतिशत तक होगी और अलग-अलग मॉडल व वेरिएंट के अनुसार लागू की जाएगी।

रेनो इंडिया का कहना है कि पिछले कुछ समय से कच्चे माल की लागत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा सप्लाई चेन से जुड़ी समस्याएं, परिवहन खर्च में इजाफा और वैश्विक स्तर पर ऑटोमोबाइल उद्योग पर बने मैक्रोइकोनॉमिक दबाव कंपनियों के सामने बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। इन परिस्थितियों में लागत का संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो गया है, जिसके चलते कीमतों में संशोधन करना जरूरी हो गया। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह ग्राहकों को बेहतर गुणवत्ता, आधुनिक फीचर्स और भरोसेमंद सेवाएं देने के साथ-साथ प्रतिस्पर्धी बने रहने का प्रयास जारी रखेगी।

भारतीय बाजार में रेनो फिलहाल तीन प्रमुख मॉडलों—क्विड, ट्राइबर और काइगर—की बिक्री कर रही है। इन कारों को किफायती दाम, अच्छा माइलेज और परिवारों के लिए उपयोगी विकल्प के तौर पर जाना जाता है। ऐसे में कीमतों में बढ़ोतरी का असर सीधे मध्यम वर्ग और पहली बार कार खरीदने वालों पर पड़ सकता है। कंपनी की ओर से संकेत दिए गए हैं कि दिसंबर 2025 तक ग्राहक मौजूदा कीमतों पर कार खरीद सकते हैं, इसके बाद नई दरें लागू होंगी। इस वजह से साल के आखिरी महीने में शोरूम में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

रेनो के अलावा अन्य ऑटोमोबाइल कंपनियों ने भी नए साल से कीमतें बढ़ाने की घोषणा कर दी है। मर्सिडीज-बेंज, जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया, निसान और बीएमडब्ल्यू मोटरराड जैसी कंपनियां भी जनवरी 2026 से अपने वाहनों के दाम बढ़ाएंगी। इन कंपनियों का भी तर्क लगभग समान है कि बढ़ती इनपुट लागत, महंगाई और नियामकीय बदलावों के कारण कीमतों में संशोधन अपरिहार्य हो गया है।

निसान मोटर इंडिया ने भी 1 जनवरी 2026 से अपनी कारों की कीमतों में तीन प्रतिशत तक बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। फिलहाल निसान भारतीय बाजार में मैग्नाइट मॉडल की बिक्री कर रही है, जो किफायती एसयूवी के रूप में लोकप्रिय है। कीमतों में बढ़ोतरी के बाद इस सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा और भी तेज होने की संभावना है।

कोहरे की चादर में ठहर गईं उड़ानें, वाराणसी एयरपोर्ट पर दिनभर अफरा-तफरी

(जीएनएस)। वाराणसी। पूर्वांचल में छाए घने कोहरे ने शनिवार को हवाई यातायात को पूरी तरह से जकड़ लिया। बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दृश्यता इतनी कम हो गई कि सुरक्षा कारणों से नौ उड़ानों को रद्द करना पड़ा। अचानक उड़ानें निरस्त होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और एयरपोर्ट परिसर में दिनभर बेचैनी और असमंजस का माहौल बना रहा।

सुबह से ही वाराणसी और आसपास के इलाकों में कोहरे की मोटी परत छाई रही। रनवे पर दृश्यता मानकों से नीचे चली गई, जिसके चलते एयरपोर्ट प्रशासन ने उड़ानों के संचालन को लेकर सतर्कता बरती। एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से जारी सूचना के अनुसार, यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उड़ानों को रद्द करने का फैसला लिया गया। मौसम की यह स्थिति इतनी गंभीर थी कि विमान लैंडिंग और टेकऑफ दोनों ही जोखिम भरे हो गए थे।

रद्द की गई उड़ानों में एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक, इंडिगो की छह और स्पाइसजेट की दो फ्लाइट शामिल रहीं। इनमें दिल्ली, अहमदाबाद और अन्य प्रमुख शहरों के लिए निर्धारित उड़ानें थीं। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों में नाराजगी और चिंता दोनों देखने को मिली। कई यात्री घंटों तक एयरपोर्ट पर इंतजार करते रहे, जबकि कुछ ने मजबूरन ट्रेन या सड़क मार्ग से यात्रा करने का विकल्प चुना।

सर्दी के मौसम में पहले से ही यात्रा करना चुनौतीपूर्ण हो गया है और उस पर उड़ानें रद्द होने से मुश्किलें और बढ़ गईं। यात्रियों का कहना था कि उन्हें मौसम खराब होने की आशंका तो थी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होंगी, इसका अंदाजा

नववर्ष की रात अहमदाबाद अलर्ट मोड में, 31 दिसंबर को घर से निकलने से पहले यह जानना जरूरी

(जीएनएस)। अहमदाबाद में नववर्ष की पूर्व संध्या को लेकर शहर पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। 31 दिसंबर की रात को होने वाले जश्न, भीड़ और संभावित अव्यवस्था को देखते हुए नगर पुलिस ने कड़े सुरक्षा और यातायात प्रबंध लागू कर दिए हैं। यदि आप 31 तारीख की शाम या रात को घर से बाहर निकलने की योजना बना रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही आपकी खुशियों को परेशानी में बदल सकती है। नववर्ष के स्वागत के लिए शहर के होटल, कैफे, मॉल और प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर भारी भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए पुलिस ने पहले से ही विस्तृत योजना तैयार की है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है और ड्रोन, सीसीटीवी तथा मोबाइल पेट्रोलिंग के जरिए पूरे शहर पर नजर रखी जाएगी। यातायात व्यवस्था को लेकर सबसे अहम फैसला यह लिया गया है कि शहर की कुछ प्रमुख सड़कों को पूरी तरह बंद या डायवर्ट किया जाएगा। पुलिस के अनुसार 31 दिसंबर की शाम 6 बजे से लेकर 1 जनवरी की सुबह 3 बजे तक सिंधुभवन रोड और सीजी रोड पर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि अत्यधिक भीड़, जाम

और दुर्घटनाओं की आशंका को कम किया जा सके। इन सड़कों पर आमतौर पर नववर्ष की रात सबसे ज्यादा चहल-पहल रहती है, जिसके कारण पहले कई बार अव्यवस्था की स्थिति बन चुकी है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मिथखली सर्कल से कॉमर्स क्रॉसिंग होते हुए सीजी रोड की ओर सीमित यातायात की अनुमति दी जाएगी, लेकिन झजरमन क्रॉसिंग से लेकर ताज होटल तक का मार्ग पूरी तरह बंद रहेगा। ऐसे में वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना होगा। विशेष रूप से एसपी रिंग रोड को वैकल्पिक रूट के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, एसजी हाईवे पर भी अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी और यात्री वाहनों के अलावा अन्य भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। सुरक्षा के लिहाज से अहमदाबाद शहर को नववर्ष की रात पूरी तरह 'नो फ्लाई ज़ोन' घोषित किया गया है। इसका मतलब यह है कि ड्रोन, पैराग्लाइडिंग या किसी भी प्रकार की हवाई गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। यह कदम किसी भी संभावित खतरे को रोकने और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। पुलिस और प्रशासन का मानना है कि इस तरह के कड़े उपायों से किसी भी तरह की अराजकता पर समय रहते काबू पाया जा सकेगा। इसी बीच शहर में धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों को लेकर भी माहौल गर्माया हुआ है। क्रिसमस के बाद भी भगवा सेना द्वारा विरोध प्रदर्शन जारी है। पैलेडियम मॉल में क्रिसमस ट्री लगाए जाने को लेकर संगठन के कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई और प्रदर्शन किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। इस घटना ने भी प्रशासन को सतर्क कर दिया है, क्योंकि नववर्ष की रात ऐसे आयोजनों और प्रदर्शनों से कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका रहती है। भगवा सेना के अध्यक्ष कमल रावल ने अपने बयान में कहा कि उनके कार्यकर्ता मॉल में किसी प्रकार का हंगामा करने नहीं गए थे, बल्कि धर्म से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना चाहते थे। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि सार्वजनिक और व्यावसायिक स्थानों पर केवल क्रिसमस और नए साल जैसे आयोजनों को ही क्यों बढ़ावा दिया जाता है, जबकि सनातन धर्म के पर्व और उत्सवों को समान महत्व क्यों नहीं दिया जाता। हालांकि पुलिस ने साफ कर दिया है कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। नगर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे नववर्ष का जश्न जिम्मेदारी के साथ मनाएं। शराब पीकर वाहन न चलाएं, यातायात नियमों का पालन करें और पुलिस द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सम्मान करें। अनावश्यक रूप से बंद सड़कों पर जाने से बचें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। पुलिस का कहना है कि नागरिकों के सहयोग के बिना इतनी बड़ी व्यवस्था को सफल बनाना संभव नहीं है। कुल मिलाकर, अहमदाबाद में 31 दिसंबर की रात को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जश्न का माहौल जरूर होगा, लेकिन सुरक्षा और व्यवस्था सर्वोपरि रखी गई है। यदि आप बाहर निकलने की योजना बना रहे हैं, तो पहले से मार्ग की जानकारी लें, समय का ध्यान रखें और नियमों का पालन करें। तभी नववर्ष की शुरुआत खुशी और सुरक्षित माहौल में हो सकेगी।

इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट भर्ती पर संकट के बादल, छात्र नेता युवराज सिंह जडेजा ने उठाए पारदर्शिता पर सवाल

(जीएनएस)। राजकोट में प्रस्तावित इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट भर्ती परीक्षा से ठीक पहले विवाद गहराता नजर आ रहा है। छात्र नेता युवराजसिंह जडेजा ने पीजीवीसीएल और जीईटीको द्वारा की जा रही भर्तियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि इन प्रक्रियाओं में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की आशंका है। उनका दावा है कि बीते समय में हुई भर्तियों के अनुभव यह संकेत देते हैं कि आगामी भर्ती भी संदेह के घेरे में है, जिससे हजारों मेहनती और योग्य अभ्यर्थियों के भविष्य पर प्रश्नचिह्न लग सकता है।

युवराजसिंह जडेजा का कहना है कि जामनगर में प्रशिक्षु लाइनमैनों की भर्ती के दौरान पहले ही घोटाले जैसे हालात सामने आ चुके हैं। उनके अनुसार, कुल 107 पदों में से करीब 35 पदों पर फर्जी उम्मीदवारों की भर्ती किए जाने के आरोप सामने आए थे, जिनकी आज तक निष्पक्ष जांच नहीं हो पाई है। इसी पृष्ठभूमि में कल होने वाली इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट भर्ती को लेकर छात्रों में गहरी चिंता और आक्रोश देखा जा रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि केवल एक स्थान तक ही यह मामला सीमित नहीं है, बल्कि गोंडल, जूनागढ़ और कच्छ जैसे क्षेत्रों में भी हुई भर्तियों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। युवराजसिंह के मुताबिक, विभिन्न केंद्रों पर एक जैसे पैटर्न में चयन, संदिग्ध दस्तावेज और

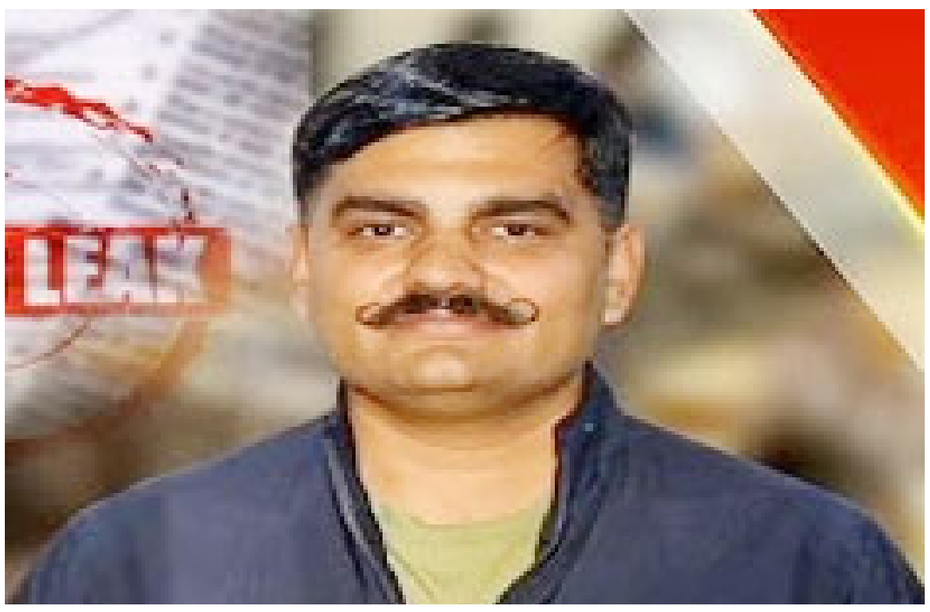

कुछ उम्मीदवारों को अनुचित लाभ मिलने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन संबंधित विभागों द्वारा इन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है।

छात्र नेता ने कहा कि यदि समय रहते इन आरोपों की गंभीरता से जांच नहीं की गई, तो इसका सीधा असर राज्य की भर्ती प्रणाली की विश्वसनीयता पर पड़ेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी लड़ाई किसी एक व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नहीं, बल्कि छात्रों के अधिकारों और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया के लिए है। उनका कहना है कि सरकारी भर्तियां पूरी तरह से खुली, पारदर्शी और जवाबदेह होनी चाहिए, ताकि योग्य उम्मीदवारों का विश्वास व्यवस्था में बना रहे।

युवराजसिंह जडेजा ने मांग की है कि कल होने वाली भर्ती से पहले सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाए और चयन प्रक्रिया पर स्वतंत्र निगरानी सुनिश्चित की जाए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई, तो आंदोलन का रास्ता भी अपनाया जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राज्य की भर्ती एजेंसियों की भूमिका और जवाबदेही पर एक बार फिर बहस तेज हो गई है, और हजारों उम्मीदवार अब प्रशासन की ओर से स्पष्ट और ठोस जवाब का इंतजार कर रहे हैं।